सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 187, नई दिल्ली । सोमवार, 16 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया . . .

03 केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का फैसला जनता के हित में....

06 कल के कार्यबल के लिए आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

08 देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, पंजीकरण शुरू....

विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली आईएएस शहजाद आलम ने दिल्ली से बाहरी राज्यों में जानें वाली जनता को वाहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, जानें

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली से अन्य राज्यों में जानें के जनता के लिए सार्वजनिक सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित सवारी सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी दिल्ली में बने अंतर राजकीय बस टर्मिनल का प्रयोग करना पसंद करते हैं। यह वह बस टर्मिनल है जहां सभी राज्यों से चलने वाली सरकारी/सरकारी निकाय की बसे या अंतर राजकीय स्टेज कैरिज परमिट प्राप्त बसे आकर खड़ी होती है जिन पर जनता द्वारा भरोसा और विश्वास किया जा सकता है। जनता के विश्वास का फायदा उठाते हुए दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारी शहजाद आलम जो की डीटीडीआईसी के भी आला अधिकारी के पद पर आसीन थे के द्वारा दिल्ली के अंतर राजकीय बस टर्मिनलो में उन वाहनों को अंदर आने और सवारी भरने की इजाजत दे दी जो मोटर वाहन नियम के विरुद्ध है। इस आदेश के जारी करने से डीटीडीआइसी कम्पनी को मोटी रकम की कमाई और वाहन मालिकों को भी मोटी कमाई का रास्ता दे दिया।

अध्याय 4
परिवहन वाहनों का नियंत्रण
पर्यटक परमिट नियम सं. 85.

पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें.- धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन मोटर कैब से भिन्न पर्यटक वाहन को दिए जाने वाले प्रत्येक पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थातः- (6) पर्यटक वाहन को स्टेज कैरिज द्वारा प्रयुक्त किसी बस स्टैण्ड पर पार्क नहीं किया जाएगा और ऐसे बस स्टैण्ड से प्रचालित नहीं किया जाएगा।

(1) परमिट धारक प्रत्येक यात्रा के संबंध में वाहन में ले जाए जाने वाले पर्यटक यात्रियों की तीन प्रतियों में सूची तैयार कराएगा, जिसमें निम्नलिखित पूर्ण विवरण दिया जाएगाः-

(क) यात्रियों का नाम,
(ख) यात्रियों का पता,
(ग) यात्रियों की आयु,
(घ) प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु।

118[(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची की एक प्रति पर्यटक वाहन में रखी जाएगी और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जाएगी तथा दूसरी प्रति परमिट धारक द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।]

(3) पर्यटक वाहन या तो अपनी यात्रा शुरू करेगा या अपनी यात्रा समाप्त करेगा, परिपत्र या अन्यथा, गृह राज्य में, इस शर्त के अधीन कि वाहन गृह राज्य से 119 [तीन महीने] से अधिक की अवधि के लिए बाहर नहीं रहेगा। परमिट धारक यह देखेगा कि गृह राज्य में पर्यटक वाहन की प्रत्येक वापसी की सूचना परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को दी जाए: बशर्ते कि जहां अनुबंधित यात्रा गृह राज्य के बाहर समाप्त होती है, वहां वाहन को उस राज्य के भीतर या उस राज्य से किसी अन्य राज्य के लिए किराये पर नहीं दिया जाएगा, सिवाय गृह राज्य में किसी बिंदु तक वापसी यात्रा के लिए।

(4) पर्यटक वाहन केवल गृह राज्य में या गृह राज्य में तथा राज्य के बाहर स्थित स्थानों के वृत्ताकार दौरे संचालित कर सकेगा, यदि ऐसे वृत्ताकार दौरे गृह राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक, ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व के स्थानों के भ्रमण के लिए अनुमोदित सूची में हों तथा दौरे का पहले से ही विधिवत विज्ञापन किया गया हो।

(5) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत एजेंट किराएदार को रसीद जारी करेगा और उसकी प्रति उसके पास उपलब्ध रखी जाएगी तथा मांगे जाने पर उसे अधिनियम के तहत या उसके तहत दस्तावेज मांगने के लिए सशक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) पर्यटक वाहन को स्टेज कैरिज द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी बस स्टैंड पर पार्क नहीं किया जाएगा और ऐसे बस स्टैंड से संचालित नहीं किया जाएगा।

(7) पर्यटक वाहन को सफेद रंग से रंगा जाएगा तथा वाहन के बाहरी भाग के मध्य में पांच सेंटीमीटर चौड़ाई का नीला रिबन लगा होगा तथा वाहन के दोनों ओर साठ सेंटीमीटर व्यास के घेरे में ₹पर्यटक₹ शब्द लिखा होगा।

117 सा.का.नि. 338(अ), दिनांक 26-3-1993 द्वारा (26-3-1993 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

11 उप-नियम (2) सा.का.नि. 338(अ), दिनांक 26-3-1993 द्वारा प्रतिस्थापित (26-3-1993 से)।119 सा.का.नि. 338(अ), दिनांक 26-3-1993 द्वारा ₹दो मास₹ के स्थान पर प्रतिस्थापित (26-3-1993 से)।

(8) परमिट धारक पर्यटक वाहन के सामने ऊपरी हिस्से में पीले रंग का बोर्ड प्रदर्शित करेगा। ब्लॉक में लॉटरी के साथ ₹पर्यटक मानदंड₹ शामिल है।

*विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा इस आदेश को जारी करने का आधार / कारण जो भी कागजों में दिखाया गया है उसकी जांच अनिवार्य है क्योंकि नियम और कानून के बाहर जाकर जनता के विश्वास से घात करना और जनता को विश्वसनीय सार्वजनिक सवारी सेवा की जगह अविश्वसनीय सवारी वाहनों में भेज कर वाहन मालिकों और कम्पनी को फायदा पहुंचाना पद की शक्ति का दुरुपयोग है।

भारत एक्सप्रेस को ब्रह्मपुर-टाटा लॉन्च किया गया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वरः भारत एक्सप्रेस को ब्रह्मपुर-टाटा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल लॉन्च किया है. ब्रह्मपुर में मुख्tcयमंत्री की मौजूदगी में बंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने भाषण में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के कारण पूरा देश बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी विकसित देशों के बराबर आ गया है और विकास की एक नई लहर दौड़ गयी है। देश में शुरू हुआ।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक्सप्रेस ब्रह्मपुर-टाटा मार्ग पर ओडिशा की सिल्क सिटी को स्टील सिटी टाटा से जोड़ेगी. ट्रेन ब्रह्मपुर से टाटा तक 9 घंटे 5 मिनट में पार करेगी और बालूगांव, खुर्दा, भुवनेश्वर, कटक, जखपुरा, हरिचंदंपुर, क्योंझरगढ़ आदि स्टेशनों पर भी रुकेगी। ब्रह्मपुर एक समृद्ध शहर है, लेकिन इसकी रेशम साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे ब्रह्मपुरी पट कहा जाता है। इसके लिए ब्रह्मपुर को ₹रेशम नगरी₹ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, ब्रह्मपुर हमारे राज्य का एक प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्र है। बंदे भारत एक्सप्रेस के कारण शहर के पर्यटन और व्यापार क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।

दिल्लीवासियों का सफर होगा आसान, सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 100 मोहल्ला बसें

दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस सेवा इसी महीने से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने के बाद सरकार उद्घाटन की तारीख तय कर रही है। इन बसों को 10-10 किमी के दायरे में चलाने की योजना है। मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित मोहल्ला बस सेवा इसी माह से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने से सरकार उद्घाटन की तारीख तय कर रही है।

माना जा रहा है कि नौ मीटर लम्बी एसी इलेक्ट्रिक बसें इसी माह के आखिरी सप्ताह से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 100 मोहल्ला बसों के साथ इस सेवा की शुरूआत 15 सितंबर से होने वाली थी, लेकिन अब यह इस महीने के आखिर में शुरू होगी।

इन बसों को कुशक नाला व गाजीपुर डिपो में रखा गया है। मोहल्ला बसों के चलने से फर्स्ट माइल व लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार ने 2025 तक 2,180 एसी मोहल्ला बसों को चलाने की योजना बनाई है।

मोहल्ला बसों के लिए रूट तैयार

अभी पीएमआई कंपनी की 9 मीटर लम्बी इलेक्ट्रिक बसें सरकार को मिलनी शुरू हुई हैं। अगले महीने से जेबीएम कंपनी की भी बसें आनी शुरू हो जाएंगी। मोहल्ला बसों के लिए रूट तैयार कर लिया गया है। इन बसों को 10-10 किमी के दायरे में चलाने की योजना है।

जिन इलाकों में 12 मीटर लम्बी बसें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां भी मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। ये बसें लोगों को घर के पास से बस टर्मिनलों, मेट्रो स्टेशनों व मुख्य सड़कों तक आवागमन को सुगम बनाएंगी। मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है।

फुल चार्ज होने पर 120-130 किमी चलेगी बस

बस एक बार फुल चार्ज होने पर 120-130 किमी चल सकेगी। इन बसों में 25 प्रतिशत सीटें (6 सीटें) गुलाबी हैं, जो विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए आरक्षित, महिलाओं को इन बसों में भी किराया नहीं लगेगा।

मोहल्ला बसों में किराया दिल्ली सरकार की 12 मीटर लंबी एसी बसों के समान ही होगा। मोहल्ला बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए 16 डिपो तैयार किए जा रहे हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे दो नए अंडरपास

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के आसपास के गांवों सेक्टरों और सोसाइटियों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नोएडा प्राधिकरण दो नए अंडरपास बनाने जा रहा है। एक अंडरपास सुल्तानपुर गांव और दूसरा झट्टा गांव में बनाया जाएगा। इन अंडरपास के बनने से 30 आवासीय और सेक्टर-15 गांव के लोगों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी।

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के आसपास बसे गांव, सेक्टर व सोसाइटी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। आने जाने के लिए शहरवासी एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल न करें। आसानी से इधर से उधर शहर में आ जा सके।

इसके लिए एक्सप्रेस-वे पर दो नए अंडरपास बनाने जा रहा है। एक अंडरपास एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित सुल्तानपुर गांव (एक्सप्रेस-वे पर 6.10 किमी चैनेज पर) और दूसरा झट्टा गांव (एक्सप्रेस-वे पर 16.900 किमी चैनेज पर) पर तैयार किया जाएगा। परियोजना पर प्राधिकरण की ओर से 237 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है।

इससे 30 आवासीय और सेक्टर-15 गांव के लोगों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी। बता दें कि परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) दिल्ली इंट्रीग्रेटेड मल्टी माडल ट्रांजिट (डीम्ट्स)तैयार की है, जिसे प्राधिकरण की टेक्निकल ऑडिट सेल (टीएसी) से पास कर आईआईटी से वैट कराने के लिए भेजा गया है।

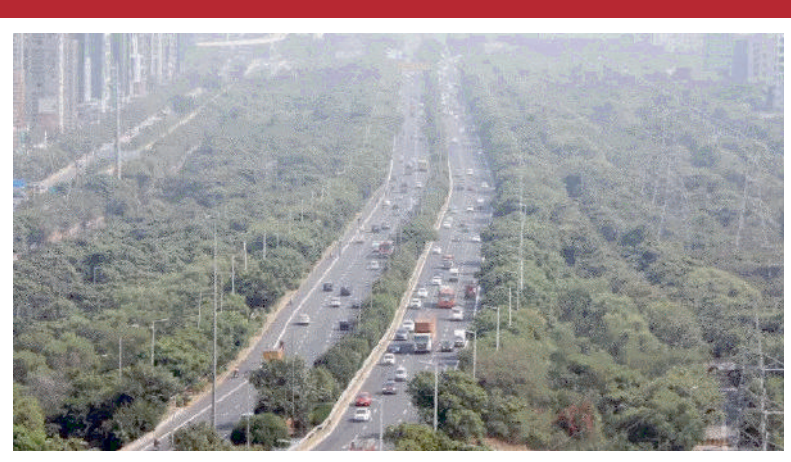

मंजूरी मिलते ही योजना को धरातल पर उतरने का काम शुरू होगा। अभी दोनों जगह छोटे अंडरपास बने है। यहां बड़े वाहन अटक जाते हैं, लंबा जाम लग जाता है। इसके पास ही चार लेन का बड़ा अंडरपास बनाया जाएगा। बड़े अंडरपास बनने से जाम की समस्या दूर हो जाएगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर पिछले दो साल में तीन नए अंडरपास बनकर तैयार हुए हैं। यह अंडरपास सेक्टर-96, 142, 152 में बनाये गए हैं। इनके बनने से एक्सप्रेसवे के दोनों ओर गांव, सेक्टर में जाने की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है।

डाया फ्रॉम तकनीक से होगा निर्माण

झट्टा व सुल्तानपुर अंडरपास निर्माण के लिए डाया फ्राम तकनीक का चयन किया है। इसमें बगैर खुदाई के डाया फ्राम वाल कास्ट की जाएगी। इसके बाद दो तरफ जमीन के अंदर यह दीवार बनाकर उसके ऊपर अंडरपास की छत ढाल दी जाएगी। नीचे दोनों दीवारों व छत के बीच की मिट्टी खोदाई कर निकाली जाएगी। इसके बाद नीचे की सड़क का काम शुरू होगा। इसी तरह से दोनों लेन का काम प्राधिकरण करवाएगी। इस कारण कुछ दिनों तक यातायात संचालन प्रभावित रहेगा।

नए बनने वाले दोनों अंडरपास की स्थिति

पहला

झट्टा अंडरपास (एक्सप्रेस-वे पर 16.900 किमी चैनेज पर सेक्टर-145, 146 155 और 159 के बीच बनाया जाएगा।)

प्रस्तावित लंबाई : 800 मीटर
अनुमानित : 131 करोड़
लभांवित होने वाले क्षेत्र : नवविकसित / विकासाधीन औद्योगिक सेक्टर-151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162 एवं समीपस्थ 9 ग्राम

दूसरा

सुल्तानपुर अंडरपास (एक्सप्रेस-वे पर 6.10 किमी चैनेज पर सेक्टर-128, 129, 132 और 108 के बीच बनेगा।)

प्रस्तावित लंबाईः 731 मीटर
अनुमानितः 106 करोड़
लभांवित होने वाले क्षेत्रः सेक्टर-104, 105, 106, 107, 108, 110, 80, 81, 82, 83, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, फेस-2, एनएसईजेड एवं 11 ग्राम

अब तक एक्सप्रेस-वे पर यहां बन चुके अंडरपास

प्रशासनिक भवन अंडरपास- सेक्टर-96 से एमिटी यूनिवर्सिटी (नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस-वे 2.36 किमी चैनज पर)

एडवंट अंडरपास- सेक्टर-142 से सेक्टर-168 (नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस-वे 10.300 किमी चैनेज पर)

कोंडली अंडरपास- सेक्टर-147 से सेक्टर-150 (नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस-वे 19.400 किमी चैनज पर)

एक्सप्रेस-वे पर पांच अंडरपास बनाये जाना थे। इसमें तीन का निर्माण पूरा हो चुका है। दो नए अंडरपास बनाने की दिशा में काम चल रहा था, जिसमें डीपीआर को आईआईटी से प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बड़ी आबादी लाभांवित होने वाली है।

-संजय कुमार खत्री, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

गणपति उत्सव

वैसे तो गणेश उत्सव केवल परंपरा मात्र नहीं है यह एक अनुष्ठान है, और अनुष्ठान हमेशा पूरी आस्था- विश्वास और प्रबल पुरुषार्थ से किए जाते हैं।

अनुष्ठान ऐसे स्थान पर किए जाते हैं जहां का वातावरण- भौगोलिक परिस्थितियां उस अनुष्ठान के अनुकूल हो। या फिर हमारा इतना दृढ़ पुरुषार्थ हो कि हम वहां का वातावरण और वहां की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकें।

अनुष्ठान में हुड़दंग, अनुशासनहीनता, अपवित्रता, शास्त्र नियमों की अवहेलना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी भी अनुष्ठान में अनुशासनहीनता व अपवित्रता होगी तो वह उत्सव-अनुष्ठान पूरी सृष्टि व जन समुदाय के लिए कदापि हितकर नहीं होता।

गणेशजी विसर्जन के समय आस्था के साथ-साथ प्रकृति व पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखें। आपने गणेश जी की 10 दिन तक विधिवत पूजा उपासना की है अतः गणेश जी का विसर्जन भी पूरे आदर व सम्मान के साथ करें।

श्री गणेश स्थापना व विसर्जन की परंपरा-:

धर्म ग्रंथों के अनुसार, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने का निर्णय लिया और इस दिव्य अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए वेदव्यास जी ने गंगा नदी के किनारे एकांत पवित्र स्थल का चुनाव किया। लेकिन, लेखन का कार्य महर्षि के वश का नहीं था। इसलिए उन्होंने इसके लिए भगवान श्री गणेश की आराधना की और उनसे प्रार्थना करी कि वे एक महाकाव्य जैसे महान ग्रंथ को लिखने में उनकी सहायत करें। गणपती जी ने सहमति दी और दिन-रात लेखन कार्य प्रारम्भ हुआ।

इसके लिए महर्षि वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही भगवान गणेश को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई थी जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरशः लिखा था। महर्षि वेद व्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की और लेखन का शुभ कार्य आरंभ कर दिया।

महाकाव्य कहे जाने वाले महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य लगातार 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी के दिन यह लेखन कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जब कथा पूरी होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने आंखें खोली तो देखा कि इस दिव्य काव्य के तेज व अत्याधिक मेहनत करने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में गणेश जी के शरीर का तापमान कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा नदी में गणेश जी स्नान करवाया।

अनंत चर्तुदशी के दिन गणेश जी के तेज को शांत करने के लिए गंगा नदी में स्नान कराया गया था, इसीलिए इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का चलन भी शुरू हुआ। पौराणिक ग्रंथों में भी श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन का उल्लेख किया गया है ।कहा जाता है कि सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में तभी से भगवान गणपती को 10 दिनों तक बैठाने की प्रथा चल पड़ी। और दसवें दिन उनका विसर्जन यानी जल स्नान करवाया जाता है।।

सर्जन व विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व-:

सर्जन की कला के साथ-साथ विसर्जन की कला भी आनी चाहिए। और गणेशोत्सव जैसे अनुष्ठान हमें सर्जन व विसर्जन दोनों की कला सीखाते हैं। और जीवन के मायने भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्हें सर्जन के साथ-साथ विसर्जन की कला सीख ली, वही व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रह सकता है और परम आनंद को प्राप्त हो सकता है।

17 सितंबर, मंगलवार को सुबह पूजा उपासना के बाद आप विधिवत श्री गणेश जी का विसर्जन करें। गणेश जी का विसर्जन करने से पहले जाने - अनजाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि (गलतियां) हुई है, उसके लिए गणेश जी से क्षमा याचना करें और सभी के मंगल की कामना करते हुए गणेश जी को पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करें।।

नाक से सांस लेना ज्यादा बेहतर है या मुंह से? जानें रनिंग के दौरान कौन सा तरीका है बेस्ट

श्वास अवचेतन है। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है - यह बस हो जाता है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, तो हममें से कई लोग इसके प्रति सामान्य से अधिक जागरूक हो जाते हैं - कभी-कभी हम अपनी हर सांस के बारे में सोचते हैं। कम और मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के दौरान, हममें से अधिकांश लोग अपनी नाक से सांस लेते हैं और अपने मुंह से सांस छोड़ते हैं। लेकिन व्यायाम जितना अधिक तीव्र होता जाता है, उतना ही हम पूरी तरह मुंह से सांस लेने लगते हैं।

हममें से अधिकांश लोग यह मानेंगे कि गहन व्यायाम के दौरान मुंह से सांस लेना सबसे अच्छी तकनीक है, क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद देता है। लेकिन सबूत इसके विपरीत दिखाते हैं - और यह कि आपकी नाक से सांस लेना वास्तव में गहन व्यायाम (जैसे दौड़ना) के दौरान उपयोग करने के लिए एक बेहतर तकनीक हो सकती है। अध्ययनों की एक श्रृंखला से पता चला है कि विभिन्न तीव्रता पर व्यायाम करते समय, मुंह से सांस लेने की तुलना में नाक से सांस लेने पर कम ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हालांकि यह कोई फ़ायदा नहीं लग सकता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब यह है कि शरीर कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए भी उतनी ही मात्रा में व्यायाम कर सकता है। यह विशेष रूप से अधिक सहनशक्ति वाले एथलीटों के लिए एक वास्तविक लाभ हो सकता है क्योंकि गति को अधिक समय तक बनाए रखना ही सफलता का मूलमंत्र है।

नाक से नहीं खींच सकते ज्यादा ऑक्सीजन

ऑक्सीजन को कार के लिए ईंधन की तरह समझें। एक कार प्रति गैलन जितने कम ईंधन का उपयोग करती है उसकी ₹ईंधन अर्थव्यवस्था₹ उतनी ही बेहतर होती है। यही बात ऑक्सीजन पर भी लागू होती है। चलते हुए पैदल यात्री जितनी कम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, व्यक्ति उतनी ही कम ऊर्जा का उपयोग करेगा (और इसलिए वह उतना ही अधिक किफायती होगा)। इसका मतलब है कि आप जल्दी थके बिना आगे दौड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा, आपकी नाक से सांस लेने से हवा की मात्रा कम हो जाती है। यह समझ में आता है, क्योंकि नाक आपके मुंह से बहुत छोटी होती है, इसलिए आप एक समय में इतनी अधिक ऑक्सीजन नहीं खींच सकते। लेकिन इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि व्यायाम करते समय लोग अपनी नाक से कम बार सांस लेते हैं, जो कम तर्कसंगत लगता है। यहां मुख्य बात यह समझना है कि हवा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर जाती है ताकि उसे फेफड़ों में जाने में मदद मिल सके। इसलिए यद्यपि मुंह की तुलना में नाक गुहा में हवा की मात्रा कम होती है, लेकिन दबाव अधिक होता है - जिसका अर्थ है कि हवा श्वसन प्रणाली में अधिक तेज़ी से प्रवेश करती है।

नाक से सांस लेने के हैं ज्यादा फायदे

इसका परिणाम यह होता है कि काम करने वाली मांसपेशियों तक ऑक्सीजन अधिक तेजी से पहुंचाई जा सकती है। प्रति सांस अधिक ऑक्सीजन भी निकलती है, जो बताता है कि एक ही व्यायाम के दौरान मुंह या नाक से सांस लेने पर हृदय गति में कोई अंतर क्यों नहीं होता है। इसलिए कम मात्रा में ऑक्सीजन आने के बावजूद, यह इंगित करता है कि हृदय को इसे मांसपेशियों तक पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यायाम के दौरान नाक से सांस लेने पर हृदय पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। शोधकर्ताओं का यह भी सुझाव है कि नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे न केवल फेफड़ों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचना आसान हो जाता है, बल्कि यह वायुजनित रोगजनकों (जैसे वायरस) को भी रोक सकता है।

व्यायाम के दौरान जागरूक रहने की जरूरत

नाइट्रिक ऑक्साइड रक्तचाप को कम करके और रक्त प्रवाह को अधिक आसानी से मदद करके ऐसा करता है, जिससे काम करने वाली मांसपेशियों तक आवश्यक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि दौड़ते समय आपकी नाक से सांस लेना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। यह आपकी गतिविधियों को अधिक किफायती बनाता है, आपके सांस लेने वाले वायुजनित कणों की मात्रा को कम करता है, व्यायाम करने वाले रक्तचाप को कम करता है और ऑक्सीजन को काम करने वाली मांसपेशियों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद करता है। अन्य प्रकार के व्यायामों (जैसे वजन उठाना) के लिए साक्ष्य कम स्पष्ट हैं, जिनमें कम, तीव्र प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यायाम ऑक्सीजन के अलावा अन्य स्रोतों से ऊर्जा खींचने पर निर्भर करते हैं - जैसे कि हमारी मांसपेशियों में संग्रहीत चीनी (ग्लूकोज)। लेकिन ये चयापचय प्रक्रियाएं, जो व्यायाम के दौरान समाप्त हो जाती हैं, उन्हें ठीक होने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। व्यायाम के बीच में आराम करते समय अपनी नाक से गहरी सांस लेने से इस प्रक्रिया को और अधिक बेहतर तरीके से होने में मदद मिल सकती है। लेकिन हालाँकि यह सब अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक लगता है, लेकिन कुछ नकारात्मक बातें भी हैं जिनके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। व्यायाम के दौरान केवल अपनी नाक से सांस लेना एक बहुत ही सीखी जाने वाली प्रक्रिया है।

इसे तुरंत लागू नहीं किया जाना चाहिए

यदि आप इसे प्रशिक्षण के बिना शुरू करते हैं, तो इससे ₹वायु भूख₹ पैदा हो सकती है - एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत प्रत्येक सांस के अंत में थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बरकरार रहती है। इससे असुविधा और हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। किसी भी चीज़ की तरह, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। अपनी नाक से सांस लेना सीखते समय, सुनिश्चित करें कि आप हवा को जबरदस्ती अंदर न डालें। कोशिश करें और इस प्रक्रिया में आराम करें। सुनिश्चित करें कि आपकी जीभ आपके मुंह के शीर्ष पर है, क्योंकि इससे जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिलता है जिससे आपकी नाक के माध्यम से गहरी सांस लेना आसान हो जाता है। हो सकता है कि आप शुरुआत में अपनी नाक और मुंह से सांस लेने के बीच बदलाव करना चाहें, जब तक कि आपको पूरी तरह से अपनी नाक से सांस लेने की आदत न हो जाए। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, प्रक्रिया उतनी ही अधिक अवचेतन होती जाएगी। व्यायाम करते समय नाक से सांस लेना बहुत प्रभावी हो सकता है। बस अभ्यास करना सुनिश्चित करें और नुकसान से बचने के लिए अपने शरीर को समायोजित होने का समय दें।

10 जोखिम कारक जो बढ़ा देते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, बदल लें ये आदतें भी

कई जोखिम कारक होते हैं, जिसके कारण महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना आदि. इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्हें आपको जानकर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है.

अक्टूबर महीने को विश्व भर में 'ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ' के रूप में मनाया जाता है. इस पूरे महीने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है. इसके लक्षणों, कारणों के बारे में जनकारी दी जाती है, ताकि महिलाएं समय रहते स्तन कैंसर (Breast Cancar)का इलाज शुरू करा कर अपने जीवन को बचा सकें. दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है. हर साल लाखों महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं. आखिर किन कारणों से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसके रिस्क फैकटर्स क्या हैं, आइए जानते हैं'

कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर?

कैंसरसेंटर डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, महिलाओं में स्तन कैंसर तब होता है, जब ब्रेस्ट की कोशिकाओं में डीएनए उत्परिवर्तित (Mutate) या परिवर्तित होने लगता है. इससे कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन को कंट्रोल करने वाले खास कार्य अक्षम हो जाते हैं. कुछ मामलों में, ये उत्परिवर्तित कोशिकाएं मर जाती हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उन पर हमला किया जाता है. लेकिन कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाता है.

ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स

कई जोखिम कारक हैं, जो महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं. इसमें कुछ ऐसे जोखिम कारक शामिल हैं, जिन्हें आप खुद से बदल नहीं सकते हैं, जैसे परिवार में ब्रेस्ट कैंसर होने की हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना. हालांकि, कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन्हें रोककर ब्रेस्ट कैंसर के विकास की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि, कई बार जिन महिलाओं में कैंसर होने का जोखिम रहता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, वहीं जिनमें रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल नहीं होते, वे इस घातक कैंसर की चपेट में आ जाती हैं. हालांकि, हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनकर इस गंभीर बीमारी से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रख सकती हैं. कुछ अन्य रिस्क फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार हैं-

-55 या इससे अधिक उम्र होने पर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है.

– ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ाने के लिए जेंडर भी है एक मुख्य कारण है. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी काफी अधिक होती है.

– जो महिलाएं प्रतिदिन एल्कोहल का सेवन करती हैं, उनमें भी स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है.

– यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो इससे ना सिर्फ डायबिटीज, हार्ट डिजीज होता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है.

-जो महिलाएं शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहती हैं या कम चलती-फिरती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम काफी अधिक होता है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें. ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग आदि करें. जितना ही आप फिजिकली एक्टिव रहेंगी, उतनी ही फिट और हेल्दी रह सकती हैं.

– कई बार पीरियड्स 12 साल की उम्र से पहले होने और 55 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज होने के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम कुछ महिलाओं में बढ़ जाता है.

– मां बनने के बाद यदि आपने अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराया, तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे में शिशु के जन्म के बाद 6 महीने जरूर ब्रेस्टफीड कराएं.

– यदि परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो इस घातक बीमारी के होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है.

– कई बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को बढ़ा सकते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन, बर्थ कंट्रोल शॉट, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल स्किन पैचेज आदि के अधिक इस्तेमाल से भी इस कैंसर के होने का रिस्क बढ़ सकता है.

मैं ईमानदार हूं तो मेरे पक्ष में वोट देना और लगता है कि गुनाहगार हूं तो मुझे वोट मत देना : केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने इस्तीफा देने की घोषणा कर दिल्ली समेत पूरे देश को चौका दिया। एक फर्जी केस में पांच महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद पार्टी मुख्यालय पर ''आप'' कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले दो दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी कि मैं ईमानदार हूं, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस दौरान केजरीवाल ने एक और बड़ा एलान किया कि मेरे साथ मनीष सिसोदिया ने भी फैसला लिया है कि वह भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे, जब जनता चुनाव में जीता कर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी। जल्द ही विधायक दल बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह, डॉ. संदीप पाठक, राघव चड्ढा, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

अगर मुझे पैसे ही कामने थे तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी- केजरीवाल

रविवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता तय करे, क्या केजरीवाल ईमानदार है या गुनाहगार है।जब जनता कहेगी कि मैं ईमानदार हूं, तभी सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा।

भगवान राम के वापस लौटने पर सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आज मैं जेल से आने के बाद अग्नि परीक्षा देने को तैयार हू।हमारे लिए शर्तें मायने नहीं रखती, लेकिन मेरी ईमानदारी मायने रखती है।

मेरा और मनीष सिसोदिया का फैसला अब दिल्ली की जनता के हाथ में है ।अंग्रेजों ने भी जेल से लिखी भगत सिंह की सारी चिट्ठियां उनके साथियों तक पहुंचाई, लेकिन मेरी एक चिट्ठी एलजी साहब तक नहीं पहुंच पाया।अंग्रेज भी स्वतंत्रता सेनानियों को एक जेल में रखते थे, लेकिन मुझे और मनीष सिसोदिया को अलग-अलग जेल में रखा गया।जनता के आशीर्वाद से

भाजपा के सारे षड्यंत्रों का मुकाबला करने की ताकत रखते है। जेल से सरकार चल सकती है, यह हमने साबित कर दिया।गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से अपील, अगर ये फर्जी केस में जेल भेजें तो इस्तीफा मत दे।

तमाम मुफ्त सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में है, जबकि बाकी राज्य घाटे मेंहैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह लोग हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये लोग बेइमान हैं, इसलिए बिजली फ्री नहीं कर सकते। कई राज्यों में इनकी 15-30 साल से सरकारें चल रही हैं, लेकिन ये स्कूल-अस्पताल ठीक नहीं कर पाए। ये अच्छा इलाज नहीं दे सके। क्योंकि ये लोग बेइमान हैं। इन्होंने ईडी-सीबीआई, दिल्ली पुलिस हमारे उपर छोड़कर ढेरों केस कर दिया। इसके बाद भी हम डट कर इनके सामने खड़े हैं और मुलाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये लोग मुझे बेइमान साबित करना चाहते हैं। मेरे उपर कीचड़ फेंक रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, सुबह-शाम मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मेरे लिए भाजपा महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मेरे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि केजरीवाल बेइमान है तो मैं एक मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा और मेरी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जीवन में इज्जत और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं कमाया।

लाल किला पर संपन्न हुआ दिल्ली लव कुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन समारोह

सुषमा रानी

लव कुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन समारोह लालकिला मैदान पर संपन्न हुआ। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि लीला मंचन समारोह 3 से 13 अक्टूबर 2024 तक होगा।दशहरा पर्व 12 अक्टूबर 2024 को पूरे देश में मनाया जाएगा। अर्जुन कुमार ने यह भी बताया कि भूमि पूजन समारोह अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कानून राज्य मंत्री , स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलो से संपन्न हुआ।

वृंदावन, मथुरा, दिल्ली के प्रसिद्ध ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हुई। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों का पटका, स्मृति चिन्ह, शक्ति की प्रतीक गदा भेंट कर सम्मान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कानून राज्य मंत्री , स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार ने कहा कि लव कुश रामलीला कमेटी हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, प्रभु श्री राम की लीला के साथ-साथ मानव सेवा और सामाजिक हित के कार्यों में संलग्न है, हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट और सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि देश विदेश में प्रख्यात रामलीला कमेटी प्रभु श्री राम का संदेश जन-जन, युवा पीढ़ी जागृत करने के उद्देश्य से रामलीला करती है यह इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

अर्जुन कुमार यह भी बताया इस बार रामलीला हाईटेक डिजिटल तरीके से होगी लगभग 100 देश के टीवी चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इस बार लीला श्री रामेश्वर धाम मंदिर की थीम पर तीन मंजिला मंच पर बॉलीवुड के लगभग 40 फिल्म स्टार लीला का मंचन करेंगे।

कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि सागर सिंह कलसी संयुक्त आयुक्त दिल्ली पुलिस, मनोज कुमार मीणा डीसीपी नॉर्थ दिल्ली पुलिस, मोहित बंसल, डिप्टी कमिश्नर एमसीडी, संदीप दीक्षित पूर्व सांसद, देवेंद्र यादव अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधायक पहलाद सिंह साहनी, अलका लांबा कांग्रेस नेता, अनिल भारद्वाज, राजेश जैन, संजय शर्मा व अन्य अतिथियों का इस अवसर पर स्मृति चिन्ह दुपट्टा पहना कर सम्मान किया गया व बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ।

भूमि पूजन समारोह के अवसर पर लीला के पवन गुप्ता, सत्यभूषण जैन , सौरब गुप्ता प्रवीण गोयल, अंकुर गोयल, मदन अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, प्रवीण सिंघल,कपिल रस्तोगी, देवेंद्र चौधरी आदि ने सभी अतिथियों का सम्मान किया।

केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का फैसला जनता के हित में- ''देर आए दुरस्त आए''

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के फैसले का दिल्ली कांग्रेस स्वागत करती है। ''देर आए दुरस्त आए'', केजरीवाल को यह उचित कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर जमानत दी है उसके बाद वे नाम के मुख्यमंत्री रह गए है, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना उनका फैसला नही मजबूरी है। दिल्ली के हित में अगर 6 महीने पहले इस्तीफा देते, तो दिल्ली में जल संकट, जल भराव के कारण हुई 30-35 लोगों की मौत नही होती, उन्हें बचाया जा सकता था।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा इस्तीफा देने के लिए "48 घंटों" का इंतजार क्यों? जब निर्णय ले लिया तो इस्तीफे की घोषणा आज ही कर देते। केजरीवाल द्वारा दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराने की मांग करना पूरी तरह नौटंकी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का कहना कि हम जनता के बीच जाऐंगे अगर जनता चाहेगी तभी मुख्यमंत्री पद पर बैठूंगा। वो दिल्लीवालों से झूठी सहानूभूति बटौरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान एकमत क्यों नही, केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव आयोग नवंबर में चुनाव कराऐं और आतिशी कहती है कि केन्द्र सरकार नवंबर में चुनाव करा ही नही सकती।

यादव ने बताया कि शराब घोटाले में जेल भेजे जाने, मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है जिसका जिक्र मैंने 13 सितंबर को उनकी जेल रिहाई के बाद किया था। श्री यादव ने कहा कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसौदिया को उपमुख्यमंत्री पद से और सत्येन्द्र जैन को जेल जाने पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब केजरीवाल भी जेल जाने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से जनता के हितों के लिए जो फैसले होने थे वो नही हुए, जिसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है।

यादव ने बताया कि दिल्ली की जनता जागरूक है और आम आदमी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम में सत्तासीन होने के बाद दिल्लीवालों को नजरअंदाज करने की प्रवृति को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुशासन और केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जवाब जरूर देगी।

सावधान! दिल्ली मेट्रो में अब क्राइम करनेवाले बख्शे नहीं जाएंगे, दिल्ली पुलिस ने कर ली खास तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो में हाल के महीनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है जिससे आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। किस समय स्टेशनों पर अपराध की घटनाएं अधिक रहीं यह निर्धारित करने के लिए 190 मेट्रो स्टेशनों से डेटा एकत्र किया गया था। इन डेटा का विश्लेषण करके पुलिस ने चोरी उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए अतिसंवेदनशील 32 मेट्रो स्टेशनों की पहचान की।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई सुरक्षा रणनीति लागू की है। इसके तहत सबसे संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर सादे कपड़ों में अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी आपराधिक घटना को होने से रोका जा सके।

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि

दिल्ली पुलिस द्वारा यात्रियों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में हाल के महीनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिससे आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। किस समय स्टेशनों पर अपराध की घटनाएं अधिक रहीं, यह निर्धारित करने के लिए 190 मेट्रो स्टेशनों से डेटा एकत्र किया गया था। इन 190 स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण करके पुलिस ने चोरी, उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए अतिसंवेदनशील 32 मेट्रो स्टेशनों की पहचान की।

32 स्टेशन संवेदनशील पाए गए

पुलिस की इन 32 संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों में कश्मीरी गेट, राजीव चौक, सीलमपुर, आनंद विहार और कालकाजी शामिल थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन रेंज) विजय सिंह ने पीटीआई को बताया, ₹हमारा लक्ष्य यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।"

उन्होंने कहा, "भीड़ के साथ घुल-मिलकर हमारे अधिकारी अधिक प्रभावी ढंग से आपराधिक गतिविधियों को रोक सकते हैं और घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं।₹ बता दें, फिलहाल दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की देखरेख सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और दिल्ली पुलिस करती है।

दिल्ली को मिला नया सीएम तो नए महापौर पर भी होगा विचार, जानिए अब तक कहां फंसा था पेंच

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर इसी महीने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है तो अगले महीने महापौर का चुनाव संभव है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नियमानुसार महापौर का चुनाव अप्रैल 2024 में होता है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से अब दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। अगर, अगले दो चार दिन में ही सीएम के इस्तीफे और फिर नए सीएम के चयन से राजधानी को नया महापौर भी मिल जाएगा। अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने और फिर जेल से बाहर होने पर कोई भी फाइल हस्ताक्षर न करने की कोर्ट की शर्तों की वजह से यह मामला लटका हुआ है।

नियमानुसार महापौर का चुनाव अप्रैल 2024 में होना था, लेकिन सीएम के जेल में होने की वजह से प्रस्तावित महापौर चुनाव के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिना सीएम की संस्तुति के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और तत्कालीन महापौर डॉ. शैली ओबेराय को महापौर चुनाव तक कार्य देखने के निर्देश दे दिए।

हर बार अप्रेल में होता है चुनाव

दिल्ली में हर वर्ष अप्रैल माह में महापौर व उप महापौर चुनाव का प्रविधान है। इसलिए 26 अप्रैल 2024 को महापौर चुनाव की तारीख तय हुई थी लेकिन राजधानी में

महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया सीएम के माध्यम से एलजी तक पहुंचती है।

अब नहीं आएगी कोई अड़चन

सीएम इस फाइल पर उस पार्षद को महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होने की संस्तुति एलजी को करते हैं जो कि चुनाव का प्रत्याशी न हो। पर, जब एलजी के पास यह फाइल बिना सीएम की संस्तुति के पहुंची तो उन्होंने नियुक्ति नहीं की थी। अब चूंकि नए सीएम के बनने के बाद इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होगी तो एमसीडी में महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्ति भी हो सकेगी और महापौर चुनाव भी हो सकेगा।

इस प्रक्रिया से नियुक्त होता है महापौर चुनाव में पीठासीन अधिकारी

निगम सचिव - कमीश्नर को यह फाइल भेजते हैं।

निगम कमीश्नर- शहरी विभाग के सचिव को फाइल भेजते हैं

शहरी विकास विभाग के सचिव- मुख्य सचिव को फाइल भेजते हैं

मुख्य सचिव - शहरी विकास विभाग के मंत्री को फाइल भेजते हैं

शहरी विकास विभाग के मंत्री- मुख्यमंत्री को यह फाइल भेजते हैं

मुख्यमंत्री - उपराज्यपाल को यह फाइल भेजते हैं।

किसके पास हैं कितने पार्षद

भाजपा- 112

आप- 127

कांग्रेस- 9

निर्दलीय- 1

रिक्त- 1

कौन-कौन है महापौर व उप महापौर पद का प्रत्याशी

महापौर पद के लिए

महेश कुमार (आप), वार्ड संख्या 84, देव नगर

कृष्ण लाल((भाजपा), वार्ड संख्या 62, शकुरपुर

उप-महापौर पद के लिए

रवींद्र भारद्वाज (आप), वार्ड संख्या-41, अमन विहार

नीता बिष्ट (भाजपा), वार्ड संख्या-247 सादतपुर

विजय कुमार (आप), वार्ड संख्या-192 त्रिलोकपुरी

रायबरेली एवं अमेठी जिसका प्रतिनिधित्व लगातार कांग्रेस ने किया की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार: राजेंद्र वर्मा

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि रायबरेली एवं अमेठी ने भारत को तीन-तीन प्रधानमंत्री दिए। इन दोनों संसदीय क्षेत्र का कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार प्रतिनिधित्व किया है, परंतु इन दोनों संसदीय क्षेत्र की स्थिति नर्क से भी बदतर है। श्री वर्मा ने कहा कि आखिर यहां की टूटी सड़क, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जल भराव गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता हैं। ऐसे में राहुल गांधी जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। देश कोई संपत्ति नहीं है, यह सभी भारतीयों का स्वाभिमान है, और सभी मिलकर इसकी रक्षा एवं विकास करते हैं। ऐसे में देश को जाति के नाम पर तोड़ना कितना उचित है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएनएल को जातियों में बांटा, अब राहुल गांधी देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के इशारे पर राहुल गांधी भारत के खिलाफ गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। परंतु देश की जनता उनके इस मंसूबे को कभी भी सफल नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनकी कार्य शैली, अनुभव एवं रणनीति से जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है वहीं विश्व में भी भारत का मान बढ़ा है।

ग्रेटर नोएडा से दादरी आना-जाना होगा आसान, बनेगा छह लेन का आरओबी; हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

आरओबी से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल व स्थानीय बस अड्डा और मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली 50 से अधिक ट्रेन ग्रेटर नोएडा टर्मिनल से होकर चलेंगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल आदि की ओर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। उन्हें दिल्ली नई दिल्ली व आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक भागदौड़ नहीं करनी होगी।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और दादरी (ग्रेटर नोएडा फेज दो) के बीच आवागमन सुगम करने के लिए पल्ला गांव के निकट बन रहे आरओबी को चार की बजाए छह लेन का बनाया जाएगा। प्राधिकरण सीईओ के प्रयास से रेलवे ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है।

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी आरओबी से जोड़ जाएगा। आरओबी के निर्माण पर तकरीबन 194 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस लागत को डीएफसीसी व इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आइआइटीजीएनएल) मिलकर वहन करेंगे।

बोड़ाकी गांव के नजदीक मल्टीमाडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को विकसित किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट हब दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ग्रेटर नोएडा और दादरी के दोनों ओर है। ट्रांसपोर्ट हब में बोड़ाकी हाल्ट का विस्तार कर उसे ग्रेटर नोएडा रेलवे टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा।

अंतरराज्यीय बस टर्मिनल व स्थानीय बस अड्डा से लोगों के लिए घर आना जाना आसान होगा। मल्टीमाडल ट्रांसपोर्ट हब तक मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी। इन परियोजनाओं की कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

कब तक पूरा होगा काम ?

अगले छह माह में परियोजनाओं का निर्माण शुरू होने की संभावना है। मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए पल्ला के पास रेलवे लाइन क्रास करने को रेलवे की तरफ से चार लेन का ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। आइआइटीजीएनएल ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे छह लेन बनाने के लिए प्रयास किया था।

आइआइटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार से इसके लिए पत्राचार किया। इन प्रयासों से ओवरब्रिज को चार के बजाए छह लेन का बनाने की मंजूरी मिल गई है।

इस पर लगभग 194 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 75 करोड़ रुपये ग्रेटर नोएडा और शेष रकम डीएफसीसी वहन करेगा। डेढ़ साल में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा व फेज दो के बीच आवाजाही होगी आसान

आरओबी के निर्माण के ग्रेटर नोएडा व ग्रेटर नोएडा फेज दो दादरी के बीच आवाजाही काफी आसान हो जाएगी।ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली आदि की तरफ से आने वालों को ग्रेटर नोएडा रेलवे टर्मिनल तक पहुंचना आसान होगा।

ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर रोड के एनएच-34 से जुड़ने से ग्रेटर नोएडा फेज दो की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। 105 मीटर रोड को एनएच 34 से जोड़ने के लिए 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

पल्ला बोड़ाकी के नजदीक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से एमएमटीएच को लाभ के साथ ग्रेटर नोएडा-दादरी के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा फेज दो दादरी की तरफ प्रस्तावित है। -

एनजी रवि कुमार, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं प्रबंधन निदेशक आइआइटीजीएनएल

देव बनकर दानिश ने की युवती से दोस्ती, एक साल तक बनाता रहा हवस का शिकार; ऐसे खुला राज

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवती को मंदिर में पूजा करने भी ले जाता था जिससे उसे उसके धर्म पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती की। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किराये कमरे में एक वर्ष तक उसके साथ रहा। वह युवती के साथ मंदिर में पूजा करने भी जाता था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

हापुड़ की युवती ने पुलिस को बताया कि वह साहिबाबाद में मार्केटिंग की नौकरी करती है। डेढ़ वर्ष पहले वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई थी। इस दौरान उसकी एक युवक से मुलाकात हुई। युवक ने अपना नाम देव बताया। उसने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। उसकी युवक से फोन पर बात होने लगी और दोस्ती हो गई।

शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म

सात अप्रैल 2023 को युवक उसे अपने साथ साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एक होटल में ले गया। वहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसके गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। युवक ने मसूरी थाना क्षेत्र की कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर उसके साथ रहने लगा। एक वर्ष तक उसे अपने साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी ने बहानेबाजी कर कराया गर्भपात

आरोपित उसके साथ मंदिर में पूजा करने भी जाता था। जिस वजह उसके धर्म पर शक नहीं हुआ। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। 22 जून 2024 को उसने आरोपित को गर्भवती होने के बारे में जानकारी दी। आरोपित ने बहानेबाजी कर उसका गर्भपात करा दिया। जिसका उसने विरोध किया था। इस बीच आरोपित उसे छोड़कर चला गया। तभी उसे युवक के धर्म के बारे में पता चला कि उसका असली नाम दानिश है। वह धौलाना के बड़ा बाजार का रहने वाला है।

युवक के परिजन ने युवती को निकाल दिया

एक जुलाई को वह आरोपित के घर पहुंची तो युवक के परिवार वालों ने उसे धक्का देकर भगा दिया। उसने हापुड़ पुलिस से इसकी शिकायत की थी। हापुड़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले को साहिबाबाद कोतवाली में ट्रांसफर कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश उपाध्याय ने बताया कि आरोपित दानिश उर्फ देव को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद की वेव सिटी में प्लॉट खरीदकर घर बनाना मुश्किल, खाली पड़े हैं 450 खरीदारों के भूखंड

गाजियाबाद की वेव सिटी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। किसानों के विरोध के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। 450 से अधिक खरीदारों के प्लॉट एक दशक से अधिक समय से खाली पड़े हैं। पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से करीब 388 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कराया गया था।

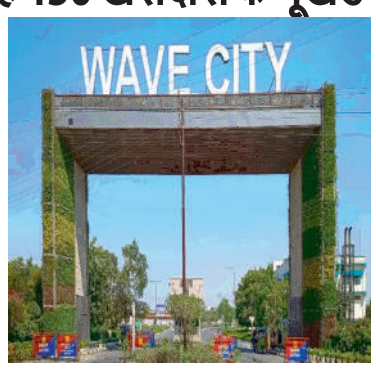

गाजियाबाद। घर बनाने के लिए वेवसिटी में प्लॉट लेकर बनाना खरीदारों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। निर्माण कार्य कराने के दौरान किसानों की ओर से विरोध किया जाता है।

ऐसे करीब 450 खरीदारों के प्लॉट एक दशक से अधिक समय से खाली पड़े हैं। कुछ लोगों ने विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप है।

वेवसिटी बननी थी टाउनशिप

वेवसिटी विकासकर्ता की ओर से 2025 में टाउनशिप के लिए स्थानीय किसानों से जमीन खरीद शुरू की थी। वेवसिटी टाउनशिप को चार हजार एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित करना था। अधिकांश भूमि को सीधे किसानों से खरीदा गया था, जिसमें कुछ किसानों ने जमीन खरीद में सहमति नहीं दी थी।

ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से करीब 388 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कराया गया, जिसमें बिल्डर की ओर से 450 से अधिक प्लॉट काटे गए थे, जिसे वर्ष 2007 से लेकर 2015 के बीच अलग-अलग खरीदारों को बेचा गया।

हाईकोर्ट पहुंचा अधिग्रहण का मामला

अधिग्रहण का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां से अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही पाया और किसानों के केस को खारिज किया गया। पुलिस और प्रशासन की मदद से बिल्डर ने 388 एकड़ भूमि पर विकास कार्य कराए गए, जिसका विरोध करने पर किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए।

यहां ऐसे प्लॉट के करीब 450 खरीदारों के समक्ष घर बनाने को लेकर समस्या आ रही है। निर्माण कार्य आरंभ करने पर किसान विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस कार्यवाही न होने पर उन्होंने बिल्डर और प्राधिकरण में गुहार लगाई है।

नोएडा में घर और दुकान बनाने का मौका अथॉरिटी निकालेगी 1190 प्लॉट की योजना

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा प्राधिकरण शहर के अलग-अलग सेक्टर में खाली 1190 प्लॉट की योजना निकालेगा। इनमें से कुछ प्लॉट औद्योगिक कुछ आवासीय कुछ कामर्शियल कुछ संस्थागत और कुछ फैसिलिटी के लिए हैं। ये प्लॉट या तो आवंटित नहीं हैं या फिर इन पर निर्माण नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने इन प्लॉट का वर्तमान स्टेटस जानने के लिए निर्देश दिए हैं।

नोएडा।शहर के अलग-अलग सेक्टर में 1190 प्लॉट खाली है। यह प्लॉट औद्योगिक, आवासीय, कामर्शियल, संस्थागत और फैसिलिटी के है। यह प्लॉट या तो आवंटित नहीं है यदि है तो इन पर निर्माण नहीं किया गया है।

प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने निर्देश दिए कि इन प्लाट का वर्तमान स्टेटस क्या है। यदि यह प्लॉट अनावंटित है या फिर लीज डीड की शर्त के अनुसार निर्माण नहीं हुआ है तो नियमानुसार इनको निरस्त किया जाए। साथ ही योजना निकाली जाए।

बैठक में उन्होंने एनएसईजेड के पास जाम को समाप्त करने के लिए यहां क्रॉसिंग का निर्माण कराया जाए। जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ की ऊंचाई कम करना, ट्राइपोड की चौड़ाई कम करते हुए सौन्दर्यकरण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद इसकी डिटेल तैयार की जाए।

डीएनडी से सेक्टर-18 फ्लाईओवर तक एक्सप्रेस-वे का चौड़ीकरण

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के इस भाग में लगने वाले भीषण जाम की समस्या को कम करने के लिए दोनों ओर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मार्गों की सर्विस लेन को मेन कैरिज वे के साथ जोड़ते हुए रोड का सेक्शन बढ़ाया जाएगा। सीईओ ने स्थल निरीक्षण किये जाने केस लिए निर्देशित किया गया। जिसमें अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सके।

डीएससी रोड होगी मॉडल

बाटेनिकल गार्डन से दिल्ली बॉर्डर तक डीएससी मार्ग का सौन्दर्याकरण किया जाएगा। यह रास्ता करीब 9 किमी का है। इस एरिया में सड़क के दोनों ओर उद्यानीकरण, फुटपाथ री-डिजाइन, स्ट्रीट लाइट, म्यूरल, वाल पेंटिंग, वेन्डिंग जोन आदि को सम्मिलित करते हुए मार्ग को माडल रोड के रूप में विकसित कर सौंदर्गीकृत किया जाए।

ब्रह्म सरोवर

गेझा सेक्टर-93 में स्थित तालाब को ग्रामवासियों एवं समीपस्थ सेक्टरवासियों की सुविधा के लिए 1.75 एकड़ तालाब के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना सौंदर्यीकरण किया जाए। जिसमें क्षतिग्रस्त रैम्प का पुनर्निमाण किया जाए। परिक्रमा के लिए 3 मीटर चौड़ा पाथ-वे, ग्रीन एरिया, सरोवर की रेलिंग एवं सरोवर के अंदर स्टोन पिचिंग का प्रविधान है।

लेक-पार्क

एनजीटी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नोएडा परिक्षेत्र में पूर्व विद्यमान तालाब, जो अस्तित्व में नहीं है इनके स्थान पर अन्यत्र वाटर बॉडीज विकसित की जा रही है। इस क्रम में सेक्टर-167 में 29.72 एकड़ में लेक पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 4.70 एकड़ क्षेत्र में झील विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

कृषि सुधारों से बढ़ती आर्थिकी

हम उम्मीद करें कि तीन सितंबर को सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन सात योजनाओं तथा 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में बेहतर बदलाव का परिदृश्य है´

हाल ही में प्रधानमंत्री की अगुआई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 14000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं फसल विज्ञान पर 3979 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2291 करोड़ रुपए के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दी गई है। पिछले कुछ समय से जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा था। लेकिन मोदी सरकार की हालिया पहल से कृषि क्षेत्र और किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सात योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और कृषि उन्नयन के प्रयासों से आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 3 सितंबर को विश्व बैंक के द्वारा जारी 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार व ग्रामीण मांग में तेजी के चलते भारत की विकास दर 7 फीसदी के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई देगी। रिपोर्ट में वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। मानसून में सुधार, निजी खपत व बढ़ते निर्यात से भी भारतीय जीडीपी को मजबूती मिल रही है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। पूरे देश के कोने-कोने में बेहतर मानसून के लाभ दिखाई देने लगे हैं। बेहतर मानसून से ग्रामीण इलाकों में खपत तेजी से बढ़ रही है।

बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। ऐसे में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन गांवों में उपभोक्ताओं की खरीददारी भी उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। निःसंदेह सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना समय की मांग है। सरकार के द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 व 2026-27 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। इसी तरह भारत की विकास दर के अनुमानों को ओईसीडी ने 6.2 से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 6.3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा फिच ने 7 से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने का रणनीतिक अभियान आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। इस बजट के माध्यम से कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सडक़ों को मंडियों से जोडने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढना होगा । चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए जिस तरह खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी सुनिश्चित की गई है, उसके कारगर उपयोग पर ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार कृषि भंडारण क्षमता वर्ष 2023 में 14.5 करोड़ टन थी। अब उसे वर्ष 2030 तक दोगुना बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढना होगा।

कृषि भंडारण क्षमता के भौगोलिक स्तर पर उचित वितरण की डगर पर भी सरकार को आगे बढना होगा। जहां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो अधिक भंडारण क्षमता है, वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसकी भारी कमी है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में केवल एक ही फसल रखने की व्यवस्था होती है। अन्य फसलों के भंडारण की सुविधा इनमें नहीं होती। इसलिए अब देश भर में भंडारण क्षमता को उन्नत कर इनमें सभी या एक से अधिक कृषि उपज रखने की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करें कि तीन सितंबर को सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन सात योजनाओं तथा 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के नए बजट से कृषि और ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के जो रणनीतिक कदम बताए गए हैं, उनके क्रियान्वयन पर शुरुआत से ही ध्यान दिया जाएगा। इन सबके साथ-साथ सरकार के द्वारा बेहतर मानसून की शक्ति को मु_ी में लेकर कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे में जहां छोटे किसानों व ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों की खुशियां बढ़ेंगी, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगी।

डा. जयंती लाल भंडारी

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

ईवीएफवाई ने गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगाया फास्ट चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में नए-नए प्लेयर्स इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रयास में इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव समाधान उपलब्ध कराने वाली स्टार्ट-अप कंपनी ईवीएफवाई ने दिल्ली-एनसीआर में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रवेश करने की घोषणा की है।

अपना पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन द वन, सेल्स गैलरी, सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR), सेक्टर 73, गुरुग्राम में स्थापित किया है, जो एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टेशन में डुअन गन क्षमता, यूजर इंट्रैक्शन और सिक्योरिटी के लिए RFID से लैस डिजिटल डिस्प्ले और 120 kW, 60 kW और 7.4 kW के पावर आउटपुट हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइक और थ्री-व्हीलर्स के साथ ही इलेक्ट्रिक कारों समेत ईवी मॉडल की एक पूरी रेंज की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

ईवीएफवाई का लक्ष्य अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को द्वारका एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट एरिया और न्यू गुरुग्राम समेत नए इलाकों में विस्तारित करना है।

आने वाले समय में ईवीएफवाई ईवी चार्जिंग स्टेशन सेक्टर में अपनी विस्तार की कोशिशों में 150 किलोवॉट के अल्ट्रा-फास्ट चार्जर और 350 किलोवॉट पावर आउटपुट वाले हाइपर-फास्ट चार्जर लगाएगी। ईवीएफवाई के को-फाउंडर ऋतिक शर्मा का कहना है कि ईवीफाई में हमारी टीम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में लगी है, जो ईवी ऑनरशिप और चार्जिंग को सरल बनाएगी। ईवीएफवाई जल्द ही ईवी चार्जर तक पहुंच को आसान बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता करने के लिए डेडिकेटेड ऐप लॉन्च करेगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना की घोषणा से ऑटो इंडस्ट्री में खुशी की लहर, ईवी की स्वीकार्यता बढ़ेगी

परिवहन विशेष न्यूज

घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने गुरुवार, 12 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने एक बयान में कहा, ₹दोपहिया, तिपहिया, ई-बसों और ई-एम्बुलेंस को समर्थन देने के साथ, यह योजना देश में ईवी की पहुंच बढ़ाएगी।₹ इसके साथ ही, महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने आगे कहा कि सभी सेगमेंट के लिए फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए निवेश से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। शाह ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव के साथ, हम भारत को 2030 तक इस सेगमेंट में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला देश बनते हुए देखते हैं।

टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने कहा कि हम देश को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने के इस प्रयास में सरकार और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।

ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कहा कि यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज फॉर इलेक्ट्रिक

व्हीकल्स (एनएचईवी) के कार्यक्रम निदेशक अभिजीत सिन्हा ने कहा कि ई-ट्रकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव में प्रदान की गई 500 करोड़ रुपये की राशि ई-ट्रकों के लिए 3 दिन पहले जारी किए गए 500 करोड़ रुपये के मिश्रित जलवायु वित्तपोषण साधन के साथ गेम चेंजर बन सकती है, जबकि चेन्नई में इनके तकनीकी परीक्षण शुरू हो रहे हैं। इस पीपीपी साधन से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को पाटने के लिए निजी पूंजी से मिलान अनुदान की भूमिका निभाने की उम्मीद है।

ईवी, हाइब्रिड, प्लग-इन-हाइब्रिड भारत के स्वच्छ ऊर्जा ऑटो क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे: रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

एलारा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का ईवी की ओर रुख केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही निर्भर नहीं होगा बल्कि इसमें हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड भी शामिल होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड का संयोजन देश को केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर ले जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ईवी बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 2023 में वैश्विक ईवी बिक्री 14 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें भारत में 90 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य 30 प्रतिशत ईवी पैठ हासिल करना है, जिसमें विस्तारित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली और नए ईवी मॉडल जारी करने जैसे प्रमुख सक्षमकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया के चीफ ग्रोथ ऑफिसर गौरव गुप्ता के अनुसार अगले 5-6 सालों में लगभग 200,000 चार्जर की आवश्यकता होगी, जिसमें हर 50 वाहनों के लिए 1 चार्जर होगा। CY30 तक कनेक्टेड कार अपनाने की दर 75-80 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद है और ADAS अपनाने की दर 45 प्रतिशत तक पहुँचनी चाहिए, जिससे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अधिग्रहण अधिक आकर्षक हो जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों में से एक सॉफ़्टवेयर-परिभाषित वाहनों SDV का उदय है। ये वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ़्टवेयर और इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को एकीकृत सिस्टम में एकीकृत करने पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहन उन्नत सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं जिनका मुद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे ओईएम को अपने व्यवसाय मॉडल को हार्डवेयर-केंद्रित से सॉफ़्टवेयर और स्मार्ट समाधान-संचालित संचालन में बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑटोमोबिलिटी के पार्टनर और सह-संस्थापक बेविन जैकब ने कहा कि ओईएम अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करके और उपभोक्ताओं को कनेक्टेड सेवाएँ प्रदान करके स्मार्ट समाधानों से मूल्य निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, ऑन-डिमांड मोबिलिटी सेवाएं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, स्वायत्त ड्राइविंग और मोबिलिटी-एज़-ए-सर्विस द्वारा संचालित हैं, उद्योग के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र तकनीकी प्रगति, सहयोगी प्रयासों और संधारणीय गतिशीलता की ओर एक मजबूत कदम से प्रेरित एक नाटकीय बदलाव के लिए तैयार है। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन बहुआयामी होगा, जिसमें ईवी, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड अग्रणी होंगे, जिन्हें स्थानीय उत्पादन और स्मार्ट समाधानों के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।

हाईब्रिड नहीं ईवी पर हो पूरा फोकस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए बेहतर: डॉ पवन गोयनका

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस सवाल के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACe के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भारत के चमकने का समय आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र निजी संस्थाओं की सभी अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी है। एक अनुभवी ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ डॉ. गोयनका का मानना है कि ईवी न केवल शून्य उत्सर्जन पर गतिशीलता को संभव बनाते हैं बल्कि देश के तेल आयात बिल को कम करने में भी मदद करते हैं। गौरतलब है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का चौथा-पांचवां हिस्सा आयात से पूरा करता है।

डॉ. पवन गोयनका के अनुसार भारत के पास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। वे ईवी और हाइब्रिड वाहनों की तुलना को सही नहीं मानते। उनका तर्क है कि हाइब्रिड वाहन केवल 10 प्रतिशत तक उत्सर्जन कम कर सकते हैं, लेकिन वे इसे शून्य पर लाने में सक्षम नहीं हैं। डॉ. गोयनका के अनुसार भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को हाइब्रिड जैसे सेक्टरों के बजाय पूरी तरह से ईवी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर विशेष जोर देना चाहिए।

डॉ. पवन गोयनका के अनुसार 'चाहे केंद्र सरकार हो या निजी क्षेत्र के खिलाड़ी सभी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ईवी के लिए एक विश्वसनीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होना चाहिए। साथ ही भारत को ईवी के अवसर का लाभ उठाने के लिए ईवी की उच्च कीमत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।' वे बताते हैं कि आज देश में ईवी की कीमत हाइब्रिड या आईसीआई-संचालित वाहनों की तुलना में बहुत अधिक है। भले ही ईवी पर पांच प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर लागू है, लेकिन यह हाइब्रिड की दरों का एक अंश मात्र है।

चीन ने स्थानीय कार निर्माताओं से भारत में ऑटो से

परिवहन विशेष न्यूज

चीनी सरकार ने कथित तौर पर देश के स्थानीय ऑटोमोबाइल ब्रांडों से भारत में ऑटोमोटिव से संबंधित कोई भी निवेश न करने को कहा है। चीनी ईवी या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए, निर्माताओं से अपने देश तक ही उन्नत ईवी से संबंधित तकनीक को सीमित रखने को भी कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जुलाई में चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांडों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। जिसमें उनसे भारत में ऑटोमोबाइल से संबंधित निवेश न करने को कहा गया था। रिपोर्ट में इस जानकारी के स्रोत के रूप में 'मामले से परिचित लोगों' का हवाला दिया गया है।

चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार और ऑटोमोबाइल निर्माता है। साथ ही, भारत भी अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की दौड़ में आगे निकल गया है। हाल के वर्षों में भारत से ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। और जबकि घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों के मामले में चीन और भारत के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को भारत में निवेश न करने के लिए कहना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बाजार से बीजिंग के खतरे की धारणा का संकेत हो सकता है।

हालांकि, ऑटोमोबाइल की बात करें तो यह सिर्फ़ चीन बनाम भारत की प्रतियोगिता नहीं है। हाल के वर्षों में कई चीनी कंपनियों ने तेज़ी से विकास किया है, जिसमें बीवाईडी अब टेस्ला को चुनौती दे रही है। पिछले कुछ समय से स्थानीय बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है, इसलिए चीनी कंपनियां सीमाओं से परे विनिर्माण आधार स्थापित करने की सोच रही हैं। बीवाईडी पहले से ही भारत में मौजूद है और वर्तमान में तीन मॉडल पेश करती है। इसका प्रभाव क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

चेरी ऑटोमोबाइल यूरोप में और प्लांट लगाने पर भी विचार कर रही है। लेकिन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन द्वारा निर्मित ईवी पर टैरिफ़ बढ़ोतरी की हाल की घोषणाओं से इन ब्रांडों के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है। भारत में भी, सरकार की ईवी नीति भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की ऑटोमोटिव कंपनियों के आवेदनों की गहन जांच करेगी।

चीनी ईवी कंपनियों के लिए पैमाना एक बड़ा सहयोगी है। जबकि चीनी सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सब्सिडी भी विनिर्माण

लागत को कम रखने में मदद करती है, इससे ब्रांड स्थानीय स्तर पर ईवी बना सकते हैं और उन्हें विदेशी धरती पर उन कीमतों पर बेच सकते हैं, जिनका वैश्विक प्रतिद्वंद्वी मुकाबला नहीं कर सकते। कम से कम अभी तक तो नहीं।

चीनी निर्माताओं की मदद करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक उनके उत्पादों में प्रौद्योगिकी-समृद्ध घटक हैं। वे धीरे-धीरे अपने ऑटोमोबाइल की गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे हैं। इससे हाल के दिनों में 'मेड-इन-चाइना' उत्पादों पर भरोसा बढ़ा है।

इंदौर में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर चलेंगी ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

इंदौर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ई-रिक्शा के संचालन के लिए नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है। योजना है कि इंदौर में ई-रिक्शा ऑड और ईवन नंबर के आधार पर चलेंगी, यानी आधे दिन ऑड नंबर की रिक्शा चल पाएंगी और आधे दिन ईवन नंबर की रिक्शा चल पाएंगी। भविष्य में इसे एक-एक दिन के आधार पर भी बांटा जा सकता है। इससे सडक़ पर ई-रिक्शा की संख्या आधी ही रह जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इस फार्मूले को लागू करने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस योजना तैयार कर रहे हैं। इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी है। इस पर गुरुवार को हुई सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में भी चर्चा हुई थी और कलेक्टर ने इस फार्मूले को पंसद करते हुए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए थे। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत शहर की सडक़ों पर ई-रिक्शा की संख्या कम करने के लिए दिन के आधे समय यानी करीब 3 बजे तक ऑड नंबर यानी जिन गाडियां का आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हैं, उन्हें ही चलने की अनुमति दी जाएगी। दिन के बाकी आधे समय ईवन नंबर यानी जिन गाडियों का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 है, वे चल पाएंगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसकी विस्तृत योजना तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी और इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था में अगर कोई ई-रिक्शा नियमों पालन नहीं करती है तो उसे आसानी से पकड़ा भी जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ऑड और ईवन नंबर के आधार पर अगर कोई रिक्शा गलत समय पर चलती मिलेगी तो उस पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई भी कर सकेगी। इससे ई-रिक्शा चालक चाहकर भी गलत समय पर गाड़ी नहीं चला सकेंगे और यातायात बाधित नहीं होगा।

आरटीओ शर्मा ने बताया कि इस समय इंदौर आरटीओ में 9,265 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। कुछ गाडियां बाहर से भी हैं, इस तरह इनकी संख्या 10 हजार से ज्यादा है। अगर एक समय में इनमें से आधी गाडियों को ही चलने की अनुमति होगी तो शहर में अभी जहां एक साथ 10 हजार गाडियां सडक़ों पर होती है, वहीं नई व्यवस्था में इनकी संख्या घटकर 5 हजार हो जाएगी। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर हो सकेगी, साथ ही सभी को पर्याप्त सवारियां भी मिल सकेंगी और नई रिक्शा के आने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

आरटीओ शर्मा ने बताया कि इंदौर में ई-रिक्शा के लिए जो योजना तैयार की जा रही है, उसमें ऑड और ईवन नंबर के साथ ही ई-रिक्शा चालकों की सुविधा के लिए अलग रंग का प्रावधा भी रखा जा रहा है, जिससे वे तय किए गए समय से अलग समय पर चल सकेंगे। जैसे अगर दोपहर तक ऑड नंबर की रिक्शा को चलने की अनुमति है, लेकिन कोई ऑड नंबर का रिक्शा चालक शाम के समय गाड़ी चलाना चाहता है तो दोनों समय की गाडियों के लिए अलग रंग भी तय कर दिया जाएगा और ऐसे ई-रिक्शा चालक अपनी गाड़ी पर विपरित समय के रंग की पट्टी लगातार गाड़ी चला सकेंगे।

ट्रैफिक सुधार के लिए सीएम डॉ मोहन यादव के शहर उज्जैन में 10 जुलाई से रंग के आधार पर इसी तरह की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। उज्जैन में 5900 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा हैं। रजिस्टर्ड हैं और महाकाल लोक बनने के बाद इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ई-रिक्शा को दो अलग रंगों में बांटा गया है, आधे ई-रिक्शा के आगे के कांच पर पर पीले रंग की रेडियम पट्टी लगाई गई है और आधे पर लाल रंग की। पीली पट्टी लगी रिक्शा रात 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं और लाल पट्टी लगी ई-रिक्शा दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक चल सकती हैं। इससे एक समय पर सडक़ों पर ई-रिक्शा की संख्या आधी हो जाती है। अफसरों की माने तो इसके कारण उज्जैन के ट्रैफिक में भी सुधार देखा गया है।

जहां एक ओर आड-ईवन की योजना बनाई जा रही है, वहीं ई-रिक्शाओं के लिए रूट्स भी तय किए जा रहे हैं, ताकि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होने के साथ ही यात्रियों को भी सुविधा मिले। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति अगले आठ दिनों में 14 रूट तय करेगी और जल्द ही

इन पर ई-रिक्शा का संचालन शुरू करवाया जाएगा। यह निर्णय सडक़ सुरक्षा को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह, आरटीओ प्रदीप शर्मा और ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी के साथ ऑटोरिक्शा चालक और ई-रिक्शा चालकों की बैठक में लिया गया। भगवा ऑटोरिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ऑटो चालक लंबे समय से ई-रिक्शा के लिए रूट्स तय करने की मांग कर रहे हैं। इनके कारण शहर का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर कल कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि ई-रिक्शा का संचालन 14 रुट्स पर किया जाएगा, वहीं अगले 8 दिनों में एक उपसमिति ई-रिक्शा के लिए रूट्स या झोन प्लान तैयार करेगी और जल्द ही इस पर ई-रिक्शा का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ कि ई-रिक्शा का संचालन प्रमुख मार्गों पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी रफ्तार कम होती है और इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।

कल के कार्यबल के लिए आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल

विजय गर्ग

प्रासंगिक बने रहने के लिए, आपको अनुकूलनशील होने और आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने, अपने कौशल को उन्नत करने और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 2. डेटा साक्षरता और विश्लेषणात्मक कौशल हम डेटा-संचालित दुनिया में रहते हैं, और डेटा नया सोना है।

एआई-संचालित नौकरियों के लिए तैयारी करने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए, पेशेवरों को तकनीकी, विश्लेषणात्मक और सॉफ्ट कौशल का मिश्रण विकसित करने की आवश्यकता है अपने करियर को भविष्य-सुरक्षित करें: एआई-संवर्धित व्यवसायों के लिए आवश्यक 5 कौशल अपने करियर को भविष्य-सुरक्षित करें: एआई-संवर्धित व्यवसायों के लिए आवश्यक 5 कौशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अब केवल एक उभरती हुई प्रवृत्ति नहीं है; यह हमारे काम करने के तरीके को नया आकार दे रहा है और आगे बने रहने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है, इसे फिर से परिभाषित कर रहा है। जीटीआव पर लगभग आधे नए कोड अब एआई-जनरेटेड हैं, और ऐआई गुणवत्ता से समझौता किए बिना 15 प्रतिशत दैनिक कार्यों को तेजी से पूरा कर रहा है। एआई का प्रभाव निर्विवाद है, और यह यहीं रहेगा। तो, सवाल यह नहीं है कि क्या एआई नौकरी बाजार में पहले से मौजूद चीज़ों को बदल देगा। अब, यह इस बारे में है कि हम कितनी तेजी से इन तकनीकों को अपनाते हैं, कौशल बढ़ाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। इसी तरह हम अपने करियर को भविष्य में सुरक्षित बना सकते हैं, खेल में आगे रह सकते हैं और नवाचार की अगली लहर चला सकते हैं। एआई और मनुष्य के बीच तालमेल जैसे कैलकुलेटर या क्विकबुक ने अकाउंटेंट की जगह नहीं ली, एआई यहां नौकरियां छीनने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बढ़ाने के लिए है। दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके, एआई हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है जो हम सबसे अच्छा करते हैं: रचनात्मकता, निर्णय और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग में, ऐआई डेटा की कमी कर सकता है और ग्राहकों को विभाजित कर सकता है, जिससे विपणक को ऐसे अभियान तैयार करने की अनुमति मिलती है जो वास्तव में दर्शकों से जुड़ते हैं। जबकि एआई दस व्यक्तियों की टीम को सौ की तरह प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, जटिल निर्णय लेने और विश्वास बनाने के लिए मनुष्य अभी भी आवश्यक हैं। यह वह जगह है जहां एआई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है और जहां मानव कौशल फर्क लाएगा। एआई-संचालित कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल .एआई ने पांच महत्वपूर्ण एआई कौशलों की रूपरेखा तैयार की है जो भविष्य के कार्यबल के लिए

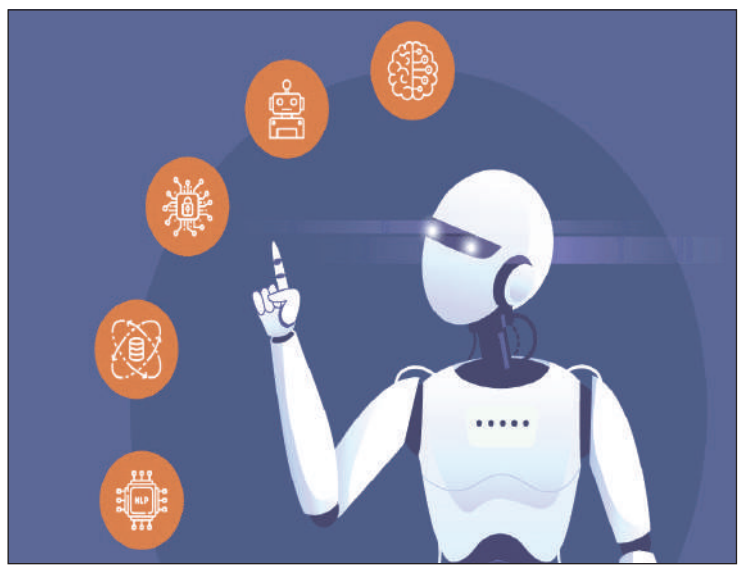

आवश्यक हैं। 1. अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना एआई और ऑटोमेशन नौकरी बाजार को पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रहे हैं। भूमिकाएँ लगातार विकसित हो रही हैं, और नई भूमिकाएँ भी उतनी ही तेज़ी से उभर रही हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए, आपको अनुकूलनशील होने और आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने, अपने कौशल को उन्नत करने और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 2. डेटा साक्षरता और विश्लेषणात्मक कौशल हम डेटा-संचालित दुनिया में रहते हैं, और डेटा नया सोना है। हर निर्णय, हर रणनीति और हर नवाचार डेटा पर निर्भर करता है। फिर भी, 43% आईटी नेताओं का कहना है कि उनकी टीमों में एआई और मशीन लर्निंग में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है। यह एक बहुत बड़ा अंतर और एक बड़ा अवसर है। आगे बढ़ने के लिए, आपको डेटा-साक्षर होने की आवश्यकता है। इसका मतलब केवल स्प्रेडशीट बनाने का तरीका जानने से कहीं अधिक है; इसका मतलब यह समझना है कि डेटा से अंतर्दृष्टि कैसे निकाली जाए, उन अंतर्दृष्टि की व्याख्या कैसे की जाए और निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। इसका मतलब है कि डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल के साथ कैसे काम करना है, सांख्यिकीय विश्लेषण करना और डेटा द्वारा बताई गई कहानियों को समझना। लेकिन बात यह है: डेटा साक्षरता केवल डेटा वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। यह मार्केटिंग से लेकर वित्त और मानव संसाधन तक सभी के लिए है। यदि आप डेटा को समझ सकते हैं, तो आप नवाचार करने, प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और किसी भी भूमिका में मूल्य बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं। 3. आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान जैसे-जैसे एआई डेटा एंट्री, शेड्यूलिंग और यहां तक कि ग्राहक सेवा के कुछ पहलुओं जैसे नियमित कार्यों को संभालता है, मानव कार्यबल को उन कार्यों को दोगुना करने की आवश्यकता होगी जो मशीनें नहीं कर सकती हैं: गंभीर रूप से सोचें और जटिल समस्याओं को हल करें। एआई पैटर्न या रुझानों की पहचान कर सकता है, लेकिन यह अस्पष्टता को दूर नहीं कर सकता है या मानवीय बारीकियों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। गंभीरसोच का अर्थ है धारणाओं पर सवाल उठाना, विभिन्न कोणों से जानकारी का विश्लेषण करना और तर्क और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना। समस्या-समाधान चुनौतियों का नया समाधान खोजने के बारे में है - एक नई बाज़ार रणनीति, एक उत्पाद सुविधा, या एक जटिल परियोजना। ये कौशल भविष्य की मुद्रा हैं। वे आपको मूल्य जोड़ने, नवाचार को बढ़ावा देने और ऐसे समाधान बनाने की अनुमति देंगे जिन्हें एआई दोहरा नहीं सकता है। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोग एआई-संचालित दुनिया में जहां रोजमर्रा का 40% काम स्वचालित होगा, सहानुभूति, सक्रिय श्रवण और संघर्ष समाधान जैसे कौशल प्रमुख कारक बन जाएंगे जो किसी व्यक्ति की प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारित करेंगे। पेशेवरों को जटिल कार्यस्थल गतिशीलता को नेविगेट करने, मजबूत रिश्ते विकसित करने और सहकर्मियों, ग्राहकों और हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करनी चाहिए। 5. नैतिक जागरूकता और वैश्विक समझ एआई सिर्फ नौकरियाँ नहीं बदल रहा है; यह दुनिया बदल रहा है. और इसके साथ ही नए नैतिक विचार भी आते हैं। जैसे-जैसे एआई व्यावसायिक प्रक्रियाओं में अधिक एकीकृत होता जा रहा है, पेशेवरों को डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और स्वचालन के सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। व्यवसाय अब स्थानीय बाजारों तक ही सीमित नहीं हैं - वे विश्व स्तर पर संचालित होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, विनियमों और बाज़ार की गतिशीलता को समझना आवश्यक है। एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य ऐसी रणनीतियाँ बनाने में मदद करता है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समावेशी, नैतिक और प्रभावी हों। एआई की शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, यह किसको प्रभावित करती है और इसके क्या अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। मजबूत नैतिक दिशा-निर्देश और वैश्विक दृष्टिकोण वाले पेशेवर इस नए परिदृश्य में कंपनियों का मार्गदर्शन करने में अमूल्य होंगे। आगे क्या होगा एआई आपकी जगह नहीं लेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो इसका उपयोग करना जानता है वह आपकी जगह ले लेगा। अगले तीन वर्षों में, 120 मिलियन से अधिक श्रमिकों को काम के इस नए युग में बने रहने के लिए पुनः प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं, तो आपको प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभार लेना होगा, प्रमाणपत्र अर्जित करना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। कंपनियों के लिए, यह वैकल्पिक नहीं है। आपको नई तकनीक को अपनाने और आगे बने रहने के लिए अपनी टीमों के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने में निवेश करना होगा। काम का भविष्य लगातार विकसित हो रहा है, और यह उन लोगों के लिए उज्ज्वल दिख रहा है जो बदलाव को अपनाने और एआई की शक्ति का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट -

संपादक की कलम से

जिद बड़ी या जिंदगी!

कोलकाता में डॉक्टर अब भी काम पर नहीं लौटे हैं। बंगाल सरकार ने संवाद और समझौते का जो प्रयास किया था, वह आंदोलनकारी डॉक्टरों की जिद ने नाकाम कर दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम जरूर सामने आया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, हाथ जोड़ कर, बंगाल की जनता से माफी मांगी है। यदि जनता चाहेगी, तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वह 'कुर्सी की भूखी' नहीं हैं, बल्कि न्याय की पक्षधर हैं। हालांकि रेप-मर्डर की शिकार डॉक्टर बिटिया के माता-पिता और आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की। इसे विपक्षियों ने मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिशें की हैं। डॉक्टरों का न्याय अलग किस्म का है, ताकि डॉक्टर बिटिया की आत्मा को सुख, शांति मिल सके। डॉक्टर मुख्यमंत्री से संवाद करने सचिवालय गए थे। उनकी संख्या 32 बताई गई है, जबकि सरकार ने 15 डॉक्टरों को ही, प्रतिनिधि के तौर पर, आमंत्रित किया था। बहरहाल बंगाल सरकार ने उस संख्या को भी अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार डॉक्टरों को समझाते रहे कि विरोध-प्रदर्शन का यह सिलसिला टूटना क्यों जरूरी है? बातचीत का सीधा प्रसारण संभव नहीं है। अलबत्ता संवाद की रिकॉर्डिंग जरूर कराई जाएगी, लेकिन आक्रोशित डॉक्टर लगातार यह सवाल करते रहे कि सीधे प्रसारण से सरकार डरती क्यों है? डॉक्टर 'नबन्ना' सचिवालय के गलियारे तक तो पहुंच गए, लेकिन उस कक्ष के भीतर नहीं गए, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2.10 घंटे से आंदोलनकारी डॉक्टरों की प्रतीक्षा कर रही थीं। नतीजतन संवाद का जो सेतु बनाया गया था, वह ढह गया। डॉक्टर लौट गए और धरना-स्थल पर जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने इस्तीफे तक की पेशकश की और बंगाल की जनता से माफी मांगी कि वह डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस लाने में नाकाम रहीं। यह ममता बनर्जी की 'भावुक राजनीति' भी हो सकती है, ताकि अधिकतर लोग उनसे नाराज न हों और समर्थन समाप्त करने पर आमादा न हो जाएं! बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में विपक्षी दल आक्रामक होकर विरोध-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर तो आंदोलित हैं ही, लेकिन उनके समर्थन में विभिन्न सामाजिक आंदोलन भी छिड़ गए हैं, लिहाजा राज्य में अराजकता की स्थिति है। सड़कों पर भीड़ है, तो पुलिसकर्मी भी हैं।

अदालतों में अलग केस चल रहे हैं। ममता की यह राजनीति आजमाई हुई है। बहरहाल डॉक्टरों का आंदोलन अब एक जिद का रूप धारण कर चुका है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें काम पर लौटने का समय दिया था, वह गुजर चुका है। शीर्ष अदालत डॉक्टरों के सरोकारों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आंदोलनकारियों को भरोसा ही नहीं है। यह जिद ही नहीं, अवमानना भी है। डॉक्टर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं, क्योंकि आरजी कर अस्पताल में इलाज न मिलने से अभी तक 27 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है और 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। यकीनन डॉक्टर बिटिया के प्रसंग पर पूरा देश गुस्से में रहा है, क्षुब्ध रहा है, असंख्य विरोध-प्रदर्शन भी किए गए हैं। डॉक्टरों के साथ सहानुभूति है, संवेदना है, क्योंकि बिटिया चिकित्सकों की सुरक्षा वाकई चिंतित सरोकार है, लेकिन काम छोड़ कर आंदोलन ही जारी रखना या जुलूस निकालना अथवा डॉक्टर होकर धरने पर खाली बैठे रहना, दरअसल अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता से मुंह मोडना है। डॉक्टर लोगों की बीमारियों के इलाज करते हुए भी विरोध जता सकते हैं। विरोध जताने के कई प्रतीक होते हैं। डॉक्टर बाजू पर काली पट्टी बांध कर भी, काम करते हुए, अपना विरोध जता सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति सरकार को दे चुकी है, लेकिन बंगाल सरकार अब भी विनम्र है, क्योंकि सरकार को कई तरह के विरोध बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। आंदोलन के 33 दिन बीत चुके हैं।

राय

अब भी 'तोता' है सीबीआई

सर्वोच्च अदालत में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत के संकेत तभी मिल गए थे, जब न्यायिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन वाले मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को ही जमानत दे दी गई थी, जबकि इस कानून में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। लंबे वक्त तक जेल में बंद रहना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार में ही उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को करीब डेढ़ साल जेल में कैद रहना पड़ा। उसके बाद भी जमानत इस आधार पर दी गई कि ट्रॉयल अभी अनिश्चित और बहुत लंबा है, लिहाजा किसी को भी उसकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। केजरीवाल और सिसोदिया एक ही केस के आरोपित हैं, लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में सीबीआई केस भी समानांतर रूप से जारी था। बीती 13 सितंबर को, अंततः, उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन न्यायाधीश भुइयां ने देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की कि उसे 'पिंजरे में बंद तोते' की धारणा से बाहर आना चाहिए और 'सीजर की पत्नी' की तरह ईमानदार होना चाहिए। यकीनन यह सीबीआई की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर गंभीर सवाल है। करीब 11 साल पहले 2013 में भी सर्वोच्च अदालत ने ही सीबीआई को 'तोता' करार दिया था, जो अपने मालिक की आवाज ही सुनता है। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ही, देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई पर, ऐसी टिप्पणियां कर कमोबेश यह संदेश दे रहे हैं कि सीबीआई ईमानदार नहीं है और अपने मालिक के आदेशानुसार ही काम करती है। नतीजतन सभी गंभीर और संवेदनशील जांच-प्रक्रियाएं दांव पर रखी महसूस होती हैं। दरअसल किसी भी बड़े, विवादित और पेचीदा मामले में देश की राज्य सरकारें और आम आदमी, अंततः, मांग करते हैं कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, लेकिन सीबीआई की कार्यप्रणाली तो 'सवालिया और संदेहास्पद' है।

क्या इसके मायने ये हैं कि भारत में जांच-प्रक्रिया तटस्थ और निष्पक्ष ही नहीं है? केजरीवाल केस में जस्टिस भुइयां ने सीबीआई से सवाल पूछा था कि केस 22 महीने पहले दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी की याद 2024 में क्यों आई? इस दौरान एजेंसी क्या करती रही? जब ईडी केस में जमानत दे दी गई, तो उसके एकदम बाद ही आरोपी को गिरफ्तार क्यों किया गया? जाहिर है कि कुछ संदेह तो होते हैं। इसी संदर्भ में न्यायाधीश ने 'तोते' वाली टिप्पणी की, जिसके निहितार्थ हो सकते हैं कि सीबीआई ने किसी के अदृश्य, अघोषित आदेश पर ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया हो! जमानत की शर्तों पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां मतभेदी लगे। जस्टिस भुइयां का मानना था कि जमानत की शर्तें क्यों होनी चाहिए? इस बिंदु पर उनकी आपत्ति है, लेकिन वह इससे अधिक कुछ नहीं बोलेंगे। जमानत के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, लेकिन उन पर ऐसी शर्तें थोपी गई हैं, जिनसे वह मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिन शक्तियों का मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कैबिनेट की बैठक बुला सकेंगे या नहीं। उपराज्यपाल के आदेश और आग्रह पर ही मुख्यमंत्री फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। केजरीवाल के जेल में रहने के कारण करीब 4000 फाइलें मंत्रियों के पास लंबित पड़ी हैं। क्या बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने मंत्रियों को नीतिगत आदेश दे सकते हैं या नहीं? बहरहाल हम लोकतंत्र में रहते हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी उस लोकतंत्र के हिस्से हैं। अदालत ने केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया है। अभी तक वह मासूम और बेगुनाह हैं, क्योंकि अदालत ने उन्हें दंडित नहीं किया है। केजरीवाल लोकतंत्र में ही जनादेश हासिल कर मुख्यमंत्री बने हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता जलवायु संकट को कैसे प्रभावित करती है और इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है

विजय गर्ग

जैसे-जैसे दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका दोधारी तलवार बन गई है। जबकि एआई पर्यावरण प्रबंधन के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है, यह समस्या में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे उच्च ऊर्जा खपत होती है। एआई अनुप्रयोगों को शक्ति प्रदान करने वाले डेटा केंद्र भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं, जो अभी भी जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि डेटा केंद्रों से ऊर्जा का उपयोग अगले दो वर्षों में दोगुना हो जाएगा, जो संभावित रूप से जापान जितनी ऊर्जा की खपत करेगा। यह पर्याप्त ऊर्जा खपत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाती है, जिससे जलवायु संकट और अधिक बढ़ जाता है। एआई की तीव्र वृद्धि और डेटा प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग का मतलब है कि इसके कार्बन फुटप्रिंट का विस्तार होने की संभावना है जब तक कि इन प्रौद्योगिकियों की शक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। AI डेटा केंद्रों का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? एआई डेटा केंद्र बड़ी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं और शीतलन उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। पानी का यह उपयोग पर्यावरणीय बोझ को बढ़ाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, इन डेटा केंद्रों के बुनियादी ढांचे के कारण अक्सर भूमि उपयोग में बदलाव और आवास में व्यवधान होता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है। तनावपूर्ण संसाधनों वाले क्षेत्रों में, एआई डेटा केंद्रों की अतिरिक्त मांग से पानी और ऊर्जा पर संघर्ष हो सकता है, जो अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एआई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है। एआई जलवायु मॉडल में सुधार करने, इमारतों में ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाने के लिए विशाल डेटासेट का विश्लेषण कर सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित सिस्टम मौसम के पैटर्न की अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने में मदद मिलती है। उभरती प्रौद्योगिकियों पर विश्व आर्थिक मंच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट ग्रिड, सटीक कृषि और जलवायु पूर्वानुमानों में एआई अनुप्रयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, एआई वनों की कटाई की निगरानी और वन्यजीवों पर नज़र रखने, संरक्षण प्रयासों में सहायता कर सकता है। हालाँकि, इन लाभों को एआई सिस्टम को बनाए रखने की

पर्यावरणीय लागत के विरुद्ध तौला जाना चाहिए। चुनौती इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए एआई की क्षमता का अच्छे उपयोग में निहित है। Google और ChatGPT द्वारा विकसित एक संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन। सबसे पहले, उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करके डेटा केंद्रों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। दूसरे, कम कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता के लिए एआई एल्गोरिदम को अनुकूलित करने से उनके कार्बन पदचिह्न को काफी कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही और सुधार के लिए एआई के ऊर्जा उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। नीति निर्माताओं, एआई डेवलपर्स और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच सहयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि एआई विकास स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। हॉपकिंस इंस्टीट्यूट फॉर एश्योर्ड ऑटोनॉमी ने जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने और उसे कम करने में एआई की क्षमता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जलवायु डेटा सेट विशाल हैं और विश्लेषण करने में समय लगता है, लेकिन एआई पर्यावरणीय परिवर्तनों के बारे में भविष्यवाणियों को बढ़ा सकता है, जिससे पहले ही सक्षम बनाया जा सके।शमन प्रयास. बेलिंगहैम ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अक्सर भौतिक पहलुओं पर केंद्रित होती है, लेकिन ये एक गतिशील, जीवित ग्रह से प्रभावित होते हैं। एआई बड़ी पवन चक्कियों के लिए सामग्री में सुधार करके कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है, जो शुद्ध-शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, एआई, परिवहन और स्मार्ट ग्रिड के विद्युतीकरण जैसे रुझानों के साथ मिलकर, ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करता है। मॉडल भविष्यवाणियों के साथ उपग्रह डेटा को एकीकृत करने की एआई की क्षमता अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिवर्तनों को कम करते हुए व्यापक पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करती है। एआई मॉडल में विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अनिश्चितताओं को उजागर करके और अवलोकन कार्यक्रमों में सुधार करके, सटीक जलवायु पूर्वानुमान सुनिश्चित करके निर्णयों की जानकारी देते हैं।

बचपन के दिन : विजय गर्ग

एक पौधा जो खूब सारे मीठे फल दे सकता था, एक पौधा जो विशाल छायादार पेड़ बन कर वैश्विक तापमान को कम करने में अपना आंशिक योगदान दे सकता था, उस पौधे को 'अनुशासन' के गमले में बोकर, प्रतिबंधों की काट-छांट कर हमने उसे बोनसाई बना दिया । वह बोनसाई सुंदर तो दिखेगा, सजावट के काम आएगा, हमारे घर के किसी कोने की खूबसूरती भी बढ़ाएगा, पर वह बोनसाई कभी फल नहीं दे पाएगा। वह बोनसाई कभी विशाल छायादार बनकर किसी राहगीर के सुस्ताने के लिए छांव नहीं दे पाएगा । हमने अपने बच्चों को वही बोनसाई बना दिया है। अनुशासन के नाम पर हमने बच्चों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि हम उसका कुदरती विकास नहीं होने दे रहे ।

अनुशासन सिखाने के नाम पर छोटे-छोटे बच्चों को छात्रावासों में रखा जा रहा है। बेहतर शिक्षा के नाम पर अपने परिवार से दूर किसी रिश्तेदार के घर रखकर पढ़ाया जा रहा है। हमें लग रहा है कि कक्षाओं की शिक्षा ही उसे बेहतर बनाएगी। यहां हम शायद गलत हैं। बच्चा सबसे पहले सीखता है अपनी मां से, अपने परिवार से, परिवेश से और अपने खुले वातावरण से । उसे खेलने और दौड़ने- भागने देना चाहिए। उसे गांव की गलियां माप लेने देना चाहिए, मेले घूम लेने देना चाहिए, खेत-खलिहानों में भटक लेने देना चाहिए। उसे जानने की कोशिश करने देना चाहिए कि कद्दू किसी पेड़ पर नहीं उगता और केले का पेड़ नहीं, पौधा होता है। उसे दोस्तों और परिजनों के बीच रहकर ही यह जान लेने देना चाहिए कि 'थर्सडे' को हिंदी में बृहस्पतिवार या गुरुवार कहते हैं । पापा की बहन बुआ होती हैं और मम्मी की बहन मौसी । सबसे पहले वह परिवार से ही सीखेगा। स्कूल की पढ़ाई तो वह कर ही लेगा। दरअसल, हम समझते हैं कि सुबह कोचिंग, दिनभर स्कूल और शाम में ट्यूशन लगाकर हम आदर्श अभिभावक की भूमिका में हैं। हम बच्चों के खेलने-कूदने पर प्रतिबंध लगाकर उसे अनुशासित बना रहे हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ स्कूल की कक्षाएं, होमवर्क, किताब, कापी और पाठ्यक्रम में सिमटकर वह बहुत सफल हो जाएगा या सिर्फ किताबों में डुबकी लगाकर वह नाम रौशन कर देगा। अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के बोझ तले बच्चों को दबाकर हमने जो उसे 'अनुशासन' का नाम दिया है, वक्त आने पर वही बच्चा अपनी असफलता की तख्ती एक समय आकर हमारे आपके गले में लटका जाएगा। अनुशासन के नाम पर हमने बच्चों को जिस तरह दब्बू और आत्मविश्वास से कमजोर बनाने का काम किया है, इसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा ।

किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में स्कूल की कक्षा की पढ़ाई का कम ही योगदान होता है। वह स्वयं से करके ही सीखता । वह गलतियां करके अनुभव लेकर सीखता है । गलतियां करेगा कब ? अनुभव लेगा कब? जब हम उसे इतनी आजादी देंगे। क बंदर अपने बच्चे के संगीत प्रशिक्षण पर लाखों खर्च कर दे, उसे बचपन में ही संगीत अकादमी में डाल दे, तो भी वह गाना कभी सीख नहीं पाएगा। उल्टे अपनी प्राकृतिक कलाबाजियां और गुलाटियां मारना भी भूल जाएगा। जब बंदर यह गलती नहीं करता, तो हम और आप क्यों ऐसा करते हैं ?

ऐसे तमाम लोग होंगे, जिनके बचपन के दिनों की मंडली दसवीं कक्षा तक गांव में ही रही और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। दोपहर के भोजन में खिचड़ी खाई। फिर उस समय के रुतबे वाली 'रेंजर' साइकिल ली, तो उससे स्कूल जाने के साथ-साथ स्कूल की कक्षाएं छोड़ कर चुपके से पास के कस्बे के बाजार में जाकर फिल्म भी देखे होंगे। स्कूल से घर कितनी बार शिकायतें आई होंगी । बच्चे दो दिन सुधरे, फिर अगले दिन कोई फिल्म देख आए । किराए पर लाकर सैकड़ों कामिक्स पढ़े, टीवी-सीडी भी किराए पर ही लाकर फिल्में देखी गई होंगी । खेत-खलिहानों में भटकना, क्रिकेट खेलकर दोपहर - शाम एक कर देना । पर इन्हीं सबसे बचपन में शायद सबसे ज्यादा सीखा गया होगा। सीखा भी शायद ऐसे ही जाता है। सिर्फ कक्षाओं की पढ़ाई के भरोसे रहा जाता तो मामला निल बट्टे सन्नाटा रहता । आज उस मंडली में कोई दुबई में होगा, कोई रेलवे में इंजीनियर होगा तो कोई बड़ा कारोबार कर रहा होगा। सब अपनी जिंदगी में खुश होंगे कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है। अगर हम पर भी 'अनुशासन' का, 'प्रतिबंधों' का बोझ लादा गया होता तो शायद हमारी स्थिति कुछ और होती।

मगर यहीं रुकने की जरूरत भी है। सारी गलती अभिभावकों की नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां बच्चों की भी बनती हैं। स्वच्छंद कदम के बहकने के भी खतरे अधिक होते हैं। बच्चों को सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि उनके पिताजी बेशक उनके नायक या प्रेरणा होंगे, पर वे कई बार 'सुपर हीरो' नहीं होते हैं। रक्तचाप और मधुमेह की समस्या लेकर जी रहे एक मध्यमवर्गीय पिता की अपनी सीमाएं होती हैं। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से उनकी अपनी क्षमता होती है। अगर पिता अपने बच्चों की आजादी की कद्र कर रहे हैं तो बच्चे खुद अपने आपको अनुशासित करें, यह दायित्व अपने आप जुड़ जाता है। कई गलतियों से पिता बच्चे को निकाल लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन इसके पीछे जो उनको कीमत चुकानी होती है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते । पिता और माता अपने बच्चों को पंख लगाएं, उन्हें उड़ने दें। थोड़ा भटक कर, थोड़ी देर से अपना भविष्य वे खुद तय कर लेंगे। तो अगर बच्चों के अभिभावक उनको पंख लगा रहे हैं तो उसी पंख के सहारे बच्चे भी सपरिवार खाई में कूदने से बचें।

इस हफ्ते बाजार में रहेगी चहल-पहल, 14 शेयरों की होगी लिस्टिंग और निवेश के लिए ओपन होंगे 5 नए IPO

परिवहन विशेष न्यूज

इस हफ्ते शेयर बाजार में कई कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग होगी। वहीं सब्सक्रिप्शन के लिए भी कई आईपीओ ओपन होंगे। बता दें कि सोमवार को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिस्ट होंगे। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि किस कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे और कौन-सी कंपनी के आईपीओ खुलेंगे।

नई दिल्ली। सोमवार से शुरू हुए कारोबारी सत्र में ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिस्ट होंगे। इसका मतलब है कि हफ्ते की शुरुआत ही धमाकेदार होगा। बता दें कि इस हफ्ते 14 आईपीओ (IPO) की लिस्टिंग होगी। वहीं निवेश के लिए भी 5 नए आईपीओ ओपन होंगे। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि किन शेयर की लिस्टिंग और कौन-से आईपीओ ओपन होने वाले हैं।

बाजार में उतरेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस

16 सितंबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ (Bajaj Housing Finance IPO) लिस्ट होगा। कंपनी के आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ अपने आखिरी दिन यानी 11 सितंबर को 67 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। इतने सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी ने टाटा टेक्नोलॉजीस (Tata Technologies) के आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पहले टाटा टेक्नोलॉजीस के आईपीओ को सबसे ज्यादा बोली मिली थी।

ये शेयर होंगे लिस्ट

16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच 14 कंपनी के आईपीओ लिस्ट होंगे। सोमवार को आर्केड डेवलपर्स (Arkade Developers), नॉर्दर्न आर्क कैपिटल (Northern Arc Capital), बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस (Kross) और टॉलिन्स टायर्स (Tolins Tyres) के शेयर लिस्ट होंगे। वहीं, 17 सितंबर को पीएन गाडगिल ज्वैलर्स के शेयर सूचीबद्ध होंगे।

इसके अलावा एसएमई सेक्टर में भी कई शेयर लिस्ट होंगे।

एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग (Excellent Wires and Packaging)
ट्रैफिकोल आईटीएस टेक्नोलॉजीस (Trafiksol ITS Technologies)
एसपीपी पॉलिमर्स (SPP Polymers)
गजानंद इंटरनेशनल (Gajanand International)
शेयर समाधान (Share Samadhan)
शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी (Shubhshree Biofuels Energy)
आदित्य अल्ट्रा स्टील (Aditya Ultra Steel)
विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस (Vision Infra Equipment Solutions)
माई मुद्रा फिनकॉर्प (My Mudra Fincorp)
सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स (Sodhani Academy of Fintech Enablers)

यह भी पढ़ें: Gold Import Limit: विदेश से कितना ला सकते हैं सोना, जानिए क्या कहते हैं नियम

निवेश के लिए खुलेंगे कई IPO

अगर आईपीओ की बात करें तो आर्केड डेवलपर्स आईपीओ (Arkade Developers IPO), नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ (Northern Arc Capital IPO) 16 सितंबर को निवेश के लिए ओपन होगा। यह दोनों आईपीओ 24 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे।

इसके अलावा एसएमई सेक्टर की कई कंपनी के आईपीओ निवेश के लिए ओपन होंगे।

एसडी रिटेल (SD Retail)
बाइकवो ग्रीनटेक (BikeWo GreenTech)
पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स (Paramount Speciality Forgings)
पेलाट्रो (Pelatro)
ओसेल डिवाइसेज (Osel Devices)
पॉपुलर फाउंडेशन (Popular Foundations), डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग (Deccan Transcon Leasing) और एनविरोटेक सिस्टम्स (Envirotech Systems) का आईपीओ इस हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा।

EPFO अकाउंट में आ गया ब्याज का पैसा, इन तरीकों से तुरंत चेक करें बैलेंस

EPF Account Balance Check

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हर सदस्य को ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ उठाकर यूजर आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनके अकाउंट में ईपीएफ का बैलेंस आया है या नहीं। हम आपको इस आर्टिकल में वह सभी तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हर वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज राशि ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में जमा करते हैं। कई ईपीएफ मेंबर्स अभी ब्याज राशि का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मेंबर्स के समय-समय पर चेक कर लेना चाहिए कि क्या उनके ईपीएफ अकाउंट में ब्याज की राशि आई है या नहीं। हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनके जरिये आप आसानी से ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं।

ईपीएफ ने बैलेंस चेक करने की सुविधा दी है। यूजर आसानी से वेबसाइट और ऐप के जरिये बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस के जरिये भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। हम आपको इन चारों तरीकों के बारे में बताएंगे।

UMANG App से चेक करें बैलेंस

आपको अपने फोन में उमंग ऐप (UMANG App) इंस्टॉल करना है।

इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना है।

लॉग-इन करने के बाद आपको ऐप में 'व्यू पासबुक' के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

अब स्क्रीन पर आपको बैलेंस शो हो जाएगा। इसमें आप सभी डिपॉजिट की तारीख और राशि भी चेक कर सकते हैं।

EPFO मेंबर्स पोर्टल से चेक करें बैलेंस

आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर Employees सेक्शन को सेलेक्ट करना है।

अब लॉग-इन करने के बाद 'मेंबर पासबुक' पर जाना है।

इसके बाद पीएफ डिटेल चेक करने के लिए आपको UAN नंबर और पासवर्ड डालना है।

अब स्क्रीन पर आपको अपना पीएफ पासबुक शो होगा।

मिस्ड कॉल

आप मिस्ड कॉल के जरिये भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UAN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसके बाद आपको मैसेज आएगा। इस मैसेज में आपको अपना बैलेंस पता चल जाएगा।

SMS

EPFO ने मैसेज के जरिये भी बैलेंस चेक करने की सुविधा दी है। मैसेज के जरिये बैलेंस चेक करने के लिए आपको 'UAN EPFOHO ENG' लिखकर 7738299899 पर मैसेज भेजना होगा। इसके बाद आपको रिप्लाई में बैलेंस पता चल जाएगा।

सोना नहीं चांदी के बढ़ सकते हैं भाव, कई कारणों से बदल जाएगा बाजार का रुख

सोने और चांदी की कीमतों में अंतर होता है। आज बाजार में सोना महंगा है तो चांदी के दाम कम है। हालांकि दोनों धातु महंगे में ही आते हैं। चांदी की कीमतों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में चांदी के दाम सोने से ज्यादा होंगे। इस आर्टिकल में जानते हैं कि भविष्य में चांदी महंगी क्यों होगी।

नई दिल्ली। सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर है। हालांकि, दोनों ही महंगी धातु में शामिल है। इन दोनों की कीमतों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले कुछ समय में सोना की जगह चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।

रिपोर्ट में चांदी के दाम (Silver Price) बढ़ने की वजह भी बताई गई है। वैसे अभी चांदी करीब 87 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, दूसरी तरफ सोना 7,408 प्रति ग्राम है। इससे हम अंतर लगा सकते हैं कि चांदी की तुलना में सोना कितनी महंगी धातु है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सालों में यह तस्वीर उल्टी भी हो सकती है। यानी सोने की जगह चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।

क्यों महंगा हो जाएगा सिल्वर

सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी या फिर कई चीजों में किया जाता है। जिन चीजों में भी सोने का इस्तेमाल होता है तो उसके दाम वैसे ही बढ़ जाते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हाल के वर्षों में इसके मांग में तेजी देखने को मिली है।

बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और पानी को प्योरिफाई जैसी नई तकनीकों के उपकरण में चांदी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में चांदी की मांग 46 फीसदी बढ़ सकती है। यह मांग ग्लोबली तौर पर बढ़ेगी। सिल्वर की डिमांड में जहां एक तरफ बढ़ोतरी होगी तो वहीं दूसरी तरफ इसके भंडर तेजी से कम होंगे।

ऐसे में अगर भंडार कम होता है और मांग बढ़ती है तो कीमतों में तेजी आती है। इस वजह से अनुमान जताया जा रहा है कि बढ़ते मांग और सप्लाई की वजह से आने वाले सालों में सोने से ज्यादा महंगा चांदी हो सकता है।

आपके पास है या खुलवाने की सोच रहे हैं लॉकर तो पहले पढ़ें आरबीआई के नए अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

कई लोग अपने जरूरी सामान यानी ज्वेलरी डॉक्यूमेंट रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करता है। बैंक लॉकर के नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं आरबीआई ने हाल ही में बैंक लॉकर के नई गाइडलाइन्स जारी की है। अगर आपके पास भी बैंक लॉकर है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको बैंक लॉकर न्यू गाइडलाइन्स के बारे में जान लें।

नई दिल्ली। अपने ज्वेलरी या फिर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट को घर में रखने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास सुरक्षित रखवाने में हमें अक्सर डर रहता है। हमें डर रहता है कि अगर यह खो गए, चोरी हो गए या फिर जल गए तो जीवन भर की जमा-पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। ऐसे में इन सभी की सिक्योरिटी के लिए बैंक लॉकर (Bank Locker) काफी अच्छा ऑप्शन रहता है।

अगर आप बैंक लॉकर लेने की या फिर आपके पास है तो आपको आज हम भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नए अपडेट के बारे में बताएंगे। इन नए अपडेट के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा ही बैंक लॉकर के नियम (Bank Locker Rule) तय किये जाते हैं। आरबीआई ने हाल ही में बैंक लॉकर के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है।

क्या है नई गाइडलाइन्स

आरबीआई ने लॉकर के रिन्यू करने का प्रोसेस बताया है। नए गाइडलाइन्स के हिसाब से 31 दिसंबर 2023 तक रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन करके बैंक में डिपॉजिट करना होगा।

क्या आप ओपन कर सकते हैं बैंक लॉकर

कई लोगों का सवाल होता है कि बैंक लॉकर किन्हें मिलता है। आरबीआई ने बताया कि बैंक लॉकर केवल उन खाताधारक को मिलता है जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट (Savin Account) या करंट अकाउंट (Current Account) हो। अगर कस्टमर बैंक लॉकर ओपन

करवाना चाहता है तो उसके लिए केवल पैन कार्ड (PAN card) या आधार कार्ड (Aadhaar card) की जरूरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होता है।

बैंक लॉकर नियमों से जुड़ी अन्य बातें

लॉकर लेने के लिए बैंक और ग्राहक के बीच एग्रीमेंट होता है। इन एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने के बाद ही लॉकर अलॉट किया जाता है।

लॉकर का साइज क्या होगा? यह ग्राहक द्वारा तय किया जाता है। वैसे तो बैंक लॉकर सिंगल-टायर्ड या मल्टी-टायर्ड होते हैं।

जब लॉकर ओपन हो जाता है तो बैंक कस्टमर को स्पेसिफिक नंबर की चाबी देता है और अपने पास उसका मास्टर चाबी (Master key) रखता है।

लॉकर पर कितना रेंट लगेगा यह इस बात पर तय किया जाता है कि लॉकर का साइज क्या है बैंक किस लोकेशन है। हालांकि, लॉकर ओपन होने के साथ ही बैंक कस्टमर से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है। यह डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed deposit) या कैश अमाउंट पर जमा किया जा सकता है।

शेयर मार्केट से ज्यादा गोल्ड ने दिया बंपर रिटर्न, जानिए क्यों आसमान के भाव चढ़ रहा सोना

परिवहन विशेष न्यूज

सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से तेजी देखने को मिली है। ऐसे में जो निवेशक गोल्ड और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके मन में सवाल आता है कि इन दोनों में से कहां उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी किसमें उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। हम आपको बता दें कि 2024 में अभी तक गोल्ड ने स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया।

नई दिल्ली। भारत में महिलाओं के साथ निवेशकों को भी गोल्ड काफी पसंद आता है। निवेशक अच्छे रिटर्न के लिए गोल्ड जैसे कीमती धातु में निवेश करते हैं। ऐसे में कई नए निवेशकों के मन में सवाल होता है कि क्या शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न गोल्ड दे रहा है। इसके अलावा गोल्ड खरीदारों के मन में सवाल आता है कि गोल्ड के दाम में लगातार तेजी किस वजह से हो रही है। हम आपको इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे।

गोल्ड ने दिया बंपर रिटर्न

अगर 2024 की बात करें तो इस साल गोल्ड (Gold Returns) ने शेयर मार्केट (Stock Market Returns) से ज्यादा रिटर्न दिया है। ग्लोबली गोल्ड की कीमत 2,060 डॉलर से 2,600 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई है। यानी सोने की कीमत में करीब 26 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, शेयर बाजार की बात करें तो इस साल अभी तक निफ्टी-50 करीब 16.60 फीसदी चढ़ा है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि इस साल में अभी तक गोल्ड ने शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न दिया है।

सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर एक्सपर्ट ने कहा है कि इस साल सोना 2,640 डॉलर और 2,660 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम

सोने की कीमत में जारी बढ़ोतरी के मुख्य कई वजह है। इनमें से सर्वप्रथम फेड का फैसला है। वहीं, भूराजनीतिक तनाव और बढ़त महंगाई की वजह से भी सोने की कीमतों में तेजी आ रही है।

फेड सितंबर के मध्य में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस उम्मीद की वजह से मार्केट में डॉलर कमजोर हो रहा है जिस वजह से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं।

दुनिया भर के सभी केंद्र बैंक द्वारा सोने की खरीद में तेजी आई है। जब भी गोल्ड की खरीद में तेजी आती है तो धातु के दाम में भी वृद्धि होती है।

टेक्निकल चार्ट्स में सोने की कीमतों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं।

अभी कितना है सोने के भाव

13 सितंबर 2024 (शुक्रवार) को कॉमेक्स पर गोल्ड 2,611.60 डॉलर प्रति औंस था। यह सोने का नया उच्चतम स्तर है। वहीं घरेलू बाजार में सोने की कीमत 73,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 89,244 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

पति-पत्नी में किसे मिलेगा योजना का लाभ, कब आएगी 18वीं किस्त की राशि; पढ़ें डिटेल्स

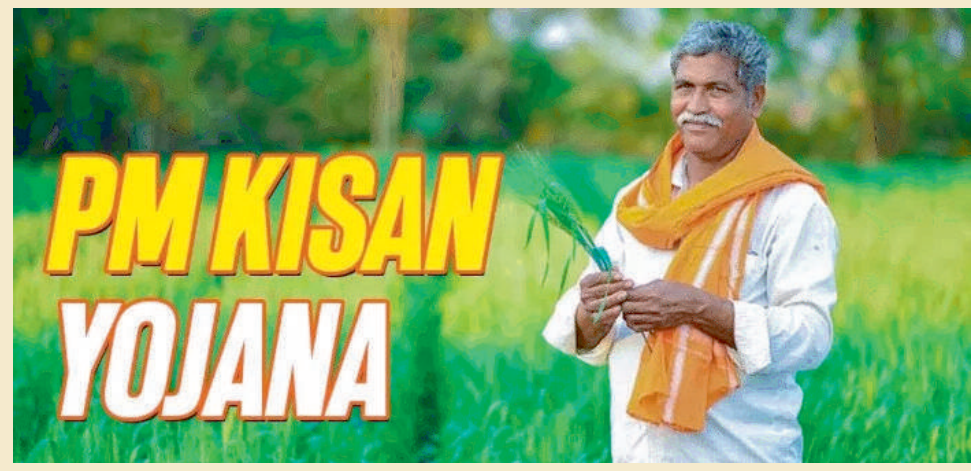

किसानों के आर्थिक लाभ देने के लिए PM Kisan Yojana शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक 17 किस्त जारी हो गई है। करोड़ों किसान 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार परिवार में किसी एक सदस्य को ही किस्त की राशि मिलती है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि पति-पत्नी में से किसे योजना का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किसानों के अकाउंट में सीधा आता है। यह राशि किसानों के अकाउंट में किस्त में आती है।

एक साल में किसानों के अकाउंट में तीन किस्त आती है। इसका मतलब है कि चार महीने के बाद किसानों के अकाउंट में किस्त आती है। पीएम किसान योजना के नियम (PM Kisan Yojana Rule) के हिसाब से योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलता है। ऐसे में सवाल है कि परिवार में पति-पत्नी में से किसे योजना का लाभ मिलता है। हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे।

पति-पत्नी में से किसे मिलेगा लाभ?

नियमों के अनुसार योजना का लाभ परिवार के सदस्यों में से किसी एक को मिलता है। ऐसे में पति-पत्नी में से उसे ही योजना का लाभ मिलेगा जिसके नाम लैंड रजिस्टर होगा। दरअसल, पीएम किसान का लाभ पाने के लिए जमीन का सत्यापन करवाना होगा।

कब आएगी अगली किस्त

जून 2024 में किसानों के अकाउंट में पीएम किसान की 17वीं किस्त आई थी। अब किसान 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की किस्त हर चार महीने के बाद जारी होती है। इस हिसाब से योजना की अगली किस्त अक्टूबर और नवंबर के बीच में आ सकती है। हालांकि, अभी तक पीएम किसान की 18वीं किस्त को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं जारी हुई है।

ये काम है जरूरी

पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी किया है। दरअसल, पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक योजना का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा होगा।

देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, पंजीकरण शुरू; ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। एनएमआर डाटाबेस है। इसमें डॉक्टरों का पंजीकरण होगा। उनकी प्रामाणिकता आधार आइडी द्वारा सत्यापित की जाएगी। एनएमआर के लांच होने से 13 लाख से अधिक डॉक्टरों का डाटा उपलब्ध होगा। एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास ने कहा कि एनएमआर तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए तैयार है।

नई दिल्ली। अब आप महज एक क्लिक कर देश के किसी भी डॉक्टर की योग्यता, अनुभव के बारे में जान सकेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकेंगे। आसानी से यह भी पता चल सकेगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं। किस डॉक्टर का लाइसेंस रद कर दिया गया है। दरअसल जल्द ही देश के हर डॉक्टर का विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा। इससे देश का डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। आप अच्छे डॉक्टर से आनलाइन परामर्श ले सकेंगे।

देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी।राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अपने पोर्टल पर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी डॉक्टरों के पास विशिष्ट आईडी होगी।

एमबीबीएस डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन

एनएमसी ने हाल ही में नोटिस में कहा कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर (आइएमआर) पर पंजीकृत सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को एनएमआर पर फिर से पंजीकरण कराना होगा। सभी मेडिकल कालेज/संस्थान, राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) पोर्टल पर आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ डाटा आम लोग भी देख सकेंगे, वहीं अन्य डाटा केवल एनएमसी, एसएमसी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), चिकित्सा संस्थानों और डॉक्टरों को ही दिखेंगे।

इस तरह होगा पंजीकरण

पंजीकरण के लिए डॉक्टरों को अपनी आधार आईडी, एमबीबीएस डिग्री की डिजिटल प्रति और उस राज्य चिकित्सा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जहां डॉक्टर पहली बार पंजीकरण कराया था।

डॉक्टर अपने योग्यता के बारे में अतिरिक्त जानकारी मैनुअली भी दर्ज कर सकेंगे। आवेदन सत्यापन के लिए आटोमेटिक तरीके से संबंधित एसएमसी तक पहुंचेगा।

एसएमसी आवेदन को समीक्षा के लिए

संबंधित कॉलेज या संस्थान को भेजेगा।

सत्यापन के बाद आवेदन एनएमसी को भेजा जाएगा। एनएमसी द्वारा सत्यापन के बाद विशिष्ट एनएमआर आइडी जारी की जाएगी।

इस प्रक्रिया के दौरान, डॉक्टर हेल्थकेयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, जो उन्हें व्यापक डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम से जोड़ेगा।

इस पोर्टल के माध्यम से एसएमसी और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी हितधारक एक ही प्लेटफार्म से लाग इन और आवेदनों का सत्यापन कर सकते हैं।

एनएमआर पोर्टल पर मिलती हैं कई सुविधाएं

एनएमआर पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें आवेदनों को ट्रैक करने, लाइसेंस निलंबित करने और एनएमआर आइडी कार्ड और डिजिटल डॉक्टर प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता शामिल है।

हरियाणा चुनावी चाट

यारों सुना है सैनी की सीट भी फँसी।
सुनकर कांग्रेस को मानों हो गई खुशी।

हुड्डा को लगता है सरकार जा रही है।
सीएम की कुर्सी बड़ी पास आ रही है।

अब तो शैलजा भी खिल-खिला रही है।
लगता सूरजेवाला को सत्ता बुला रही है।

बागियों ने दिखाया है जब से दमखम।
सारी पार्टियों की हालत हो गई टमटम।

देखों अब रूठो को सारे खूब मना रहे हैं।
बागी बड़े खास है हाथ छुड़ाएँ जा रहे हैं।

विपक्षियों को तो यहीं एक डर सता रहा है।
अमित शाह,छत्तीसगढ़ तो नहीं दोहरा रहा है।

संजय एम .तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

प्रदर्शनकारियों के पास हाईटेक हथियार, 20 सितंबर तक इंटरनेट बंद; मणिपुर पुलिस चिंतित

मणिपुर सरकार ने रविवार को पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को पांच दिनों के लिए यानी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया जबकि चार जिलों में सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। गृह विभाग ने प्रतिबंध को बढ़ाने वाले आदेश में कहा कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रविवार को चिंता जताई। डीआइजी (रेंज 1) हीरोजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने का साक्ष्य है। खाबेइसोई में हाल ही में स्वचालित हथियारों से की गई गोलीबारी में इंफाल ईस्ट कमांडो के एक अधिकारी और एक अन्य कर्मी घायल हो गए।

कानून- व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक

डीआइजी ने कहा कि हम लोगों से अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हैं। पुलिस को निशाना बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को तुरंत बंद किया जाए। कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पांच जिलों में इंटरनेट प्रतिबंध

एएनआई के अनुसार मणिपुर सरकार ने पांच जिलों में इंटरनेट निलंबन और मोबाइल डाटा सेवाओं को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवाओं के निलंबन को बढ़ा दिया।

इससे पहले राज्य सरकार ने 10 सितंबर से पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध रविवार को समाप्त होना था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया।

मोदी 3.0 सरकार में किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, पढ़ें 100 दिनों का कैसा रहा ट्रैक रिकॉर्ड

मोदी 3 .0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है लेकिन ट्रैक रिकार्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोडमैप बिल्कुल तैयार है।

नई दिल्ली: मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है, लेकिन ट्रैक रिकार्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोडमैप बिल्कुल तैयार है।

खास तौर पर पहले 100 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी चल रही थी। किसान और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए तो सरकार ने हाल में जो बड़े निर्णय किए यह छह महीने पहले से की गई इस तैयारी का ही नतीजा है।

तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का रोडमैप तैयार

हाल ही में सरकार ने महिला, युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति से लेकर हर वर्ग को भी साधने का प्रयास किया है। आम चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के रोडमैप पर काम करने के लिए कह दिया था। यह तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर उनका आत्मविश्वास ही था।

किसानों को 20,000 करोड़ रुपये बांटे

इसलिए मोदी ने नौ जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो तमाम मंत्रालयों ने 100 दिन के तैयार एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर है, इसका संकेत इससे मिलता है कि तीसरे कार्यकाल के पहले निर्णय में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

एमएसपी में वृद्धि, डिजिटल कृषि मिशन सहित कई निर्णय किए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक किसान सम्मान निधि तय करने से पहले एक अध्ययन कराया गया जिसमें पता चला कि लघु व सीमांत किसानों की कृषि लागत लगभग 5600-5700 रुपये आती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था।

बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को दी परियोजना

छह हजार रुपये सम्मान निधि देकर किसानों को इस संकट से उबारा।इसी तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को वरीयता देते हुए तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। सामाजिक कल्याण की 2ष्टि के साथ पीएम जनमन योजना चल रही है।

कचरा बीनने वालों के सशक्तीकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल कराया। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करने और विवादों के निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 भी लोकसभा में पेश हो चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का ऐलान हो गया है। कौशल विकास मिशन को निरंतर रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज बजट में घोषित किया। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 28,600 करोड़ के निवेश संग 12 औद्योगिक नोड्स को स्वीकृति और 10,600 करोड़ रुपए की विज्ञान धारा योजना जैसे फैसले लिए गए हैं।

3 आईपीएस अधिकारी हुए निलंबित, डीजी रैंक का अफसर भी शामिल; मुंबई की एक मॉडल से जुड़ा है मामला

आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एक डीजी रैंक का अधिकारी हैं। सरकार ने आइपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए रविवार को अलग-अलग आदेश जारी किए। इन अधिकारियों पर मुंबई की एक मॉडल को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बिना उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और परेशान करने का आरोप है।

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एक डीजी रैंक का अधिकारी हैं। सरकार ने आइपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए रविवार को अलग-अलग आदेश जारी किए। इन अधिकारियों पर मुंबई की एक मॉडल को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बिना

उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और परेशान करने का आरोप है।

निलंबित अधिकारियों में पूर्व खुफिया प्रमुख पी. सीताराम अंजनेयुलु (डीजी रैंक), विजयवाड़ा के पूर्व पुलिस आयुक्त क्रांति राणा टाटा (आइजी रैंक) और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (विजयवाड़ा) विशाल गुन्नी (एसपी रैंक) शामिल हैं।

कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर गिरफ्तार

मॉडल ने आरोप लगाया कि पिछली सरोकार के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुंबई में एक निगम के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माडल को इस वर्ष की शुरुआत में पिछली सरकार के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। मॉडल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।रिकार्ड के अनुसार, माडल के खिलाफ एफआइआर दो फरवरी को दर्ज की गई थी, जबकि अंजनेयुलु ने 31 जनवरी को राणा टाटा और विशाल गुन्नी को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।

16 आइपीएस अधिकारियों में शामिल थे

मॉडल ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया तथा उसे परेशान किया गया। ये तीनों अधिकारी उन 16 आइपीएस अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें निर्देश दिया गया था कि वे बिना किसी पद के दिन में दो बार डीजीपी कार्यालय में हाजिरी दर्ज कराएं। अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेदेपा ने अंजनेयुलु पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार पेगासस जासूसी साफ्टवेयर के जरिये तेदेपा महासचिव नारा लोकेश के फोन को टैप कर रही थी।

वायुसेना देगी दुश मन को मुंहतोड़ जवाब! जल्द उड़ान भरेगा LCA Mark-2; मिग-29 की जगह लेने की उम्मीद

डीआरडीओ की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देश्यीय सुपरसोनिक लड़ाकू जेट एलसीए एएफ मार्क-2 को 2025 तक भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा। एयरोनाटिक्स डेवलपमेंट अथारिटी एजेंसी बेंगलुरु के एक कर्मचारी वाजी राजपुरोहित ने बताया कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से कुल 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है जिसमें एलसीए एएफ मार्क-2 भी शामिल है।

नई दिल्ली। डीआरडीओ की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देश्यीय सुपरसोनिक लड़ाकू जेट एलसीए एएफ मार्क-2 को 2025 तक भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा। एयरोनाटिक्स डेवलपमेंट अथारिटी एजेंसी बेंगलुरु के एक कर्मचारी वाजी राजपुरोहित ने बताया कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से कुल 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें एलसीए एएफ मार्क-2 भी शामिल है।

यह मिसाइल एप्रोच चेतावनी प्रणाली जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। उम्मीद है कि अगले दशक में एलसीए मार्क-2 मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 जैसे पुराने विमानों की जगह ले लेगा।

एलसीए को 2003 में दिया गया 'तेजस' नाम

भारतीय रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित तेजस को पहली बार 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह एक सिंगल-इंजन डेल्टा विंग, मल्टी-रोल लाइट फाइटर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के सहयोग से डिजाइन किया गया है। एलसीए को आधिकारिक तौर पर 2003 में तेजस नाम दिया गया था। इसे लड़ाकू श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान माना जाता है।

क्या है इसकी खासियत ?

वायु सेना के पायलट ने एआइ-संचालित विमान निरीक्षण प्रणाली विकसित कीएएनआइ के अनुसार, भारतीय वायु सेना एमसीसी के एसयू-30 एमकेआइ पायलट स्क्वाड्रन लीडर भटकरे ने एआई-संचालित विमान निरीक्षण प्रणाली विकसित की है। यह सुविधा उन दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, जो पहले मानवीय त्रुटियों के कारण होती थीं।

भारतीय वोटर वोट देने से पहले क्या- क्या सोचता है

रागिनी सिन्हा

भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर समय-समय पर कई रिपोर्टें आती रही हैं। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि देश के मतदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय के पीछे कई पहलू होते हैं, जिनमें उम्मीदवार, पार्टी, धर्म, जाति, काम और विचारधारा शामिल हैं। लाभकारी घोषणाएँ, योजनाएँ और पैसे जैसे पहलू भी हैं। मतदान व्यवहार यानी मतदाताओं का मनोविज्ञान बताता है कि मतदाता कैसे निर्णय लेते हैं, मतदान करते समय उनके मन और दिल में क्या होता है, जिसके आधार पर वे तय करते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है।

भारतीय मतदाताओं के आधार क्या हैं ?

जाति: यह सर्वविदित है कि भारतीय मतदाताओं में जाति के प्रति विशेष आग्रह होता है। यही कारण है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं, पार्टियाँ इस आधार पर उम्मीदवार तय करती हैं कि उस क्षेत्र में किस जाति के कितने वोट हैं। इस आधार पर विश्लेषण करना चुनाव विश्लेषकों के लिए बहुत आम बात है।

धर्म: धार्मिक या समुदाय आधारित एजेंडे वाले राजनीतिक दल मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल क्षेत्र की धार्मिक आबादी को देखकर भी अपने उम्मीदवार तय करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति - आय स्तर और आर्थिक आकांक्षाएँ मतदान पैटर्न को प्रभावित करती हैं। भारत मानव विकास सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च आय स्तर वाले मतदाता आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर जोर देने वाली पार्टियों का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुफ्त खाद्य योजना, मुफ्त घर जैसी योजनाओं ने आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों के मतदान विकल्पों को प्रभावित किया है।

कौन सी पार्टी है - सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कौन सी राजनीतिक पार्टी है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के बाद किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि मतदाता निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन पर विचार करते हैं। भारत जैसे देश में, एक राजनीतिक दल की विचारधारा लोगों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद उनका प्रशासन और काम एक भूमिका निभाता है।

लीडरशिप - मतदाता अक्सर नेताओं की विश्वसनीयता, करिश्मा और क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। लोकनीति-सीएसडीएस राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2019 ने संकेत दिया कि भारत में लगभग 19 प्रतिशत मतदाताओं ने नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। मतदाता यह देखता है कि कौन सा नेतृत्व उसकी आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा कर सकता है।

पार्टी की विचारधारा - हमारे देश में, ऐसी पार्टियाँ हैं जो विभिन्न विचारधाराओं का समर्थन करती हैं - उदाहरण के लिए, समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता या क्षेत्रवाद। ये विचारधाराएँ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मायने रखती हैं। वे उनकी मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वैचारिक विचार भारतीय मतदाताओं के मतदान निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

काम - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा सरकारों का प्रदर्शन मतदाताओं के मतदान व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करता है। मुद्दे भी दिमाग पर हावी होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, आदि।

सोशल मीडिया - सोशल मीडिया का निश्चित रूप से भारत में मतदाता व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और नीलसन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक राय और प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023